RNI .NO. MPBIL / 2013/ 54381
डाक पंजीकरण संख्या MP/IDC/1619/2024-2026

संपादकः- डॉ. देवेन्द्र मालवीय

12 वर्ष

दैनिक
सद्भावना पाती
...प्राणियों में सद्भावना हो...

www.sadbhawnapaati.com Email: sadbhawnapaatinews@gmail.com इंदौर, बुधवार ● 12 फरवरी , 2025 वर्षः-12 अंक-285 मूल्य -1 रु. कुल पृष्ठ - 8

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, जगह देखें और खोल लें होटल-रिसॉर्ट

एमपी के 14 जिलों में 25 लोकेशन,वेलनेस सेंटर-टूरिज्म एक्टिविटी भी करवा सकेंगे

भोपाल। भोपाल में 24-25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होगी। इनमें उद्योगपति रिन्युएबल एनर्जी, आईटी एंड टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, माइनिंग, एमएसएमई एंड स्टार्टअप, अर्बन डेवलपमेंट आदि पर इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। टूरिज्म को लेकर एमपी टूरिज्म बोर्ड ने अभी से टेंडर खोल दिए हैं। यानी, इन्वेस्टर्स जीआईएस में आएंगे, प्रजेंटेशन देखेंगे और यदि उन्हें लोकेशन पसंद आई तो 4 से 8 घंटे के अंदर विजिट भी कर सकेंगे। जीआईएस में टूरिज्म बोर्ड इन्वेस्टर्स को कुल 25 लोकेशन दिखाएगा। ये सभी लोकेशन होटल, रिसॉर्ट, वेलनेस सेंटर और टूरिज्म एक्टिविटी से जुड़ी हैं। इनमें कुल 62 करोड़ रुपए का निवेश हो सकेगा। जबलपुर, मंदसौर, धार, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, भिंड, नीमच, बैतूल, रायसेन, बुरहानपुर, शाजापुर, शहडोल, विदिशा और अलीराजपुर। बोर्ड के अफसरों ने बताया, प्रॉपर्टी ऐसी जगह पर हैं, जहां टूरिज्म एक्टिविटी आसानी से हो सकती है। मंदसौर के गांधीसागर में तो हरियाली के बीचोबीच प्रॉपर्टी है। वहीं, धार के हेमाबर्डी में फिक्सड टेंटिंग यूनिट यानी, टेंट सिटी बनाई जा सकती है। अलीराजपुर के कट्ठीवाड़ा, बैतूल के भैंसदेही, मंदसौर के मल्हारगढ़, जबलपुर के नन्हाखेड़ा जैसी लोकेशन भी हैं। 25 में से 22 लोकेशन ऐसी हैं, जो रिसॉर्ट के लिए बेहतर है। ये लोकेशन जंगल एरिया में है। यहां होटल, वेलनेस सेंटर और इको टूरिज्म एक्टिविटी भी हो सकती है। एमपी टूरिज्म बोर्ड की प्रॉपर्टी की लोकेशन भोपाल से 3 से 8 घंटे की दूरी

पर है। जैसे- भोपाल से मंदसौर की दूरी 330 किमी, जबलपुर की दूरी 300 किमी, बैतूल की दूरी 200 किमी, शाजापुर की दूरी 150 किमी, नीमच-अलीराजपुर की दूरी 400 किमी के आसपास ही है। जहां पर कुछ ही घंटे में पहुंचा जा सकता है। इसलिए समिट के दौरान ही बोर्ड टैक्सी तैयार रखेगा। ताकि, यदि इन्वेस्टर्स का जमीन देखने का मूड हुआ तो उन्हें तुरंत मौके पर ले जाया जा सके। जीआईएस में जिन प्रमुख उद्योगपतियों को आमंत्रित किया गया है, उनमें मुकेश अंबानी, गौतम अडाणी, एन. चंद्रशेखरन, नोएल एन. टाटा, आनंद महिंद्रा, जमशेद एन. गोदरेज, संजीव पुरी, संजीव बजाज, सतीश रेड्डी, नादिर गोदरेज, पवन मुंजाल, एसएन सुब्रह्मण्यम, रिशद प्रेमजी, अजीज प्रेमजी, सलिल एस. पारेख, दिलीप संघवी, वेणु श्रीनिवासन, सुनील भारत मित्तल, बाबा एन. कल्याणी, उदय कोटक शामिल हैं।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी ममता

संजय राउत बोले-तृणमूल कांग्रेस इंडिया ब्लॉक का हिस्सा, कांग्रेस से बातचीत करनी चाहिए

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद एक बार फिर इंडिया ब्लॉक की एकजुटता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली के नतीजों के बाद ममता बनर्जी ने भी कहा कि वे 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी। इस पर शिवसेना उद्धव गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दिल्ली में कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की पार्टी राज्य में विधानसभा और लोकसभा चुनाव हमेशा अकेले लड़ती आ रही हैं लेकिन मेरा मानना है कि ममता बनर्जी

ने पश्चिम बंगाल में इंडिया ब्लॉक से नाता तोड़ लिया है। हालांकि, केंद्र में वे गठबंधन का हिस्सा हैं। इस नाते उन्हें कांग्रेस पार्टी से एक बार जरूर बात करनी चाहिए। कांग्रेस गठबंधन का सबसे बड़ा दल है। टीएमसी सूत्र ने सीएम ममता बनर्जी के हवाले से कहा, 'कांग्रेस ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मदद नहीं की। हरियाणा में एएपी ने कांग्रेस की मदद नहीं की। इसी वजह से भाजपा दोनों राज्यों में जीत गई। सभी को एक साथ होना चाहिए, लेकिन बंगाल में कांग्रेस का कुछ भी नहीं है। इसलिए अकेले चुनाव लड़ेंगे। सिब्बल बोले-गठबंधन के मसले सुलझाने होंगे।

एआई में दुनिया बदलने की ताकत यह समाज-सुरक्षा के लिए जरूरी

मोदी ने फ्रांस में कहा,राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ समिट में पहुंचे

पेरिस (एजेंसी)। पीएम मोदी का फ्रांस दौरे का मंगलवार को दूसरा दिन है। वे पेरिस में एआई समिट में शामिल हुए। उन्होंने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस में दुनिया बदलने की ताकत है। यह समाज-सुरक्षा के लिए जरूरी है। यह दिखाता है कि एआई का पॉजिटिव पोटेंशियल असाधारण है। प्रधानमंत्री ने कहा- हम एआई युग की शुरुआत में हैं, जो मानवता को बचाएगा। कुछ लोग मशीनों के इंसानों से बेहतर होने को लेकर चिंतित हैं। भारत अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज को साझा करने के लिए तैयार है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य अच्छा और सभी के लिए हो। मोदी ने कहा कि भारत ने सफलतापूर्वक कम

लागत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। डेटा एम्पावरमेंट के जरिए डेटा की ताकत को अनलॉक किया है। ये विजन भारत के राष्ट्रीय एआई मिशन की नींव है। मोदी ने समिट की शुरुआत एआई को लेकर एक उदाहरण देकर किया। उन्होंने कहा- मैं एक सरल उदाहरण देकर करना चाहता हूं। यदि आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट किसी एआई ऐप पर अपलोड करते हैं, तो यह सरल भाषा में, आपके स्वास्थ्य के लिए इसका क्या मतलब है, समझा सकता है। लेकिन यदि आप उसी ऐप से किसी व्यक्ति का बाएं हाथ से लिखते हुए चित्र बनाने को कहते हैं, तो ऐप सबसे अधिक संभावना किसी व्यक्ति को उसके दाएं हाथ से लिखते हुए दिखाएगा। पीएम ने कहा कि एआई पहले से ही हमारी अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और यहां तक कि हमारे समाज को नया आकार दे रहा है। एआई इस सदी में मानवता के लिए कोड लिख रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ कार्यक्रम की सह-अध्यक्षता कर रहे पीएम मोदी ने कहा कि हम एक ऐसे एआई युग की शुरुआत में हैं जो मानवता की राह को बचाएगा। कुछ लोग मशीनों के इंसानों से बेहतर होने की चिंता करते हैं, लेकिन हमारे सामूहिक भविष्य की कुंजी और नियति को साझा करने वाला कोई नहीं है, सिवाय हम इंसानों के। जिम्मेदारी की इस भावना को हमें समझना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि एआई के बारे में कई पूर्वाग्रह हैं जिनके बारे में हमें सावधानी से सोचने की आवश्यकता है। इसीलिए मैं अपने मित्र राष्ट्रपति मैक्रों का इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने तथा मुझे इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित करने के लिए आभारी हूं।

केजरीवाल-संजय सिंह पर एक्शन लेगा एसीबी

● विधायकों को 15 करोड़ के ऑफर के दावे पर नोटिस भेजा था,अब तक जवाब नहीं मिला

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में है। इनमें दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, मुकेश अहलावत और संजय सिंह शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार, एसीबी की तरफ से भेजे

गए नोटिस का जवाब न मिलने पर यह कदम उठाया जा सकता है। अगर एएपी की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया तो एसीबी दिल्ली पुलिस को लेटर लिखकर इन नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश करेगी। इससे पहले 7 फरवरी को एसीबी की टीम अरविंद केजरीवाल, सांसद संजय सिंह और मुकेश अहलावत के घर जांच के लिए पहुंची थी। करीब डेढ़ घंटे तक केजरीवाल के घर में जांच की, लीगल नोटिस दिया और रवाना हो गई। केजरीवाल ने दावा किया था कि भाजपा 15-15 करोड़ के ऑफर दे रही है।

भोपाल में इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी

● *सीएम बोले-बागेश्वर धाम में कैंसर हॉस्पिटल का भूमिपूजन भी करेंगे पीएम* ● *एमपी कैबिनेट में 7 नई पॉलिसी मंजूर, 20 लाख लोगों को मिलेंगे रोजगार, शिवपुरी में बनेगा एयरपोर्ट*

भोपाल। भोपाल में 22 और 23 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पीएम 23 फरवरी को छतरपुर के बागेश्वर धाम में बनने वाले कैंसर अस्पताल का भूमिपूजन करेंगे। वे रात्रि विश्राम भोपाल में करेंगे। यह जानकारी मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दी। सीएम ने बताया कि इन्वेस्टर्स समिट पर फोकस करते हुए बैठक में 7 नई पॉलिसी को मंजूरी दी गई। इनमें नई फिल्म नीति, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति, खिलौना उद्योग नीति, रक्षा उत्पादन प्रोत्साहन नीति, मेडिकल डिवाइस, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन नीति, लॉजिस्टिक पार्क नीति और पंप स्टोरेज नीति शामिल हैं। नई फिल्म नीति में युवा-महिलाओं पर केंद्रित फिल्मों पर अतिरिक्त रियायतें मिलेंगी। रोजगार और निवेश को नीतियों में प्राथमिकता में रखा गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सात महत्वपूर्ण नीतियों को मंजूरी मिली। संसदीय

कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि इन नीतियों से लगभग 20 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने बताया कि अधिकतम आर्थिक सहायता ढाई सौ करोड़ रुपये तक होगी। ये नीतियां प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। ये नीतियां फिल्म, खेती-बाड़ी, खिलौना उद्योग, रक्षा उत्पादन, मेडिकल उपकरण, इलेक्ट्रिक वाहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों से जुड़ी हैं। इसके अलावा, पर्यटन, लॉजिस्टिक पार्क और पंप स्टोरेज के लिए भी नई नीतियां बनाई गई हैं। ये नीतियां निवेश को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई हैं।

निवेशकों को झट से मिलेगी अनुमति- निवेशकों को अब आसानी से अनुमतियां मिल सकेंगी। उद्योग संवर्धन नीति में यह प्रावधान किया गया है। इसके तहत निवेशकों को एक ही जगह से सभी जरूरी अनुमतियां मिल जाएंगी। इससे उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। इससे निवेश की प्रक्रिया आसान और तेज होगी। फिल्म और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी नीतियों में बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों से इन क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने से राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने से मध्य प्रदेश फिल्म निर्माण का हब बन सकेगा। **शिवपुरी में एयरपोर्ट को मंजूरी-** शिवपुरी में नए एयरपोर्ट के निर्माण को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस एयरपोर्ट का अनुबंध पहले ही हो चुका है। जिला कलेक्टर को भूमि अधिग्रहण और अन्य कार्यों के लिए अधिकृत किया गया है। इस एयरपोर्ट के बनने से शिवपुरी का विकास होगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष को हटाने की मांग, पार्टी का इनकार

येदियुरप्पा के बेटे हैं विजयेंद्र, भाजपा ने शिकायतकर्ता विधायकों-नेताओं को ही नोटिस दिया

बेंगलुरु (एजेंसी)। कर्नाटक में भाजपा अध्यक्ष के बीवाई विजयेंद्र के खिलाफ राज्य के कुछ विधायकों और नेताओं ने असंतोष जाहिर करते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की है। हालांकि, पार्टी हाईकमान ने उन्हें हटाने से इनकार करते हुए विजयपुरा के विधायक को नोटिस जारी किया है। विजयेंद्र, पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे हैं। पार्टी हाईकमान ने

शिकायत करने वाले नेताओं को फटकार लगाते हुए विजयेंद्र के खिलाफ शिकायतों पर कार्रवाई से इनकार किया है। पार्टी ने विजयपुरा के विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतमल को नोटिस जारी कर कहा कि आप अनुशासन भंग नहीं कर सकते। नोटिस का 72 घंटे में जवाब मांगा गया है। पूर्व सीएम को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग शिकायत करने वाले नेताओं की मांग है कि विजयेंद्र को पार्टी अध्यक्ष पद से हटाकर पूर्व सीएम और सांसद बसवराज बोम्मई को कमान दी जाए। ये नेता बोम्मई से मिलकर अपनी बात रख चुके हैं।

बेंगलुरु एयरो इंडिया शो में पहुंचे 30 देशों के मिनिस्टर

राजनाथ बोले-ये शो एक और महाकुंभ, दुनिया में शांति के लिए ताकत जरूरी

बेंगलुरु (एजेंसी)। बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयरो इंडिया 2025 की शुरुआत हो चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को रक्षा मंत्रियों के कॉन्क्लेव में कहा कि कमजोर रहकर कोई देश कभी भी शांति नहीं ला सकता, केवल मजबूत होकर ही हम बेहतर दुनिया के लिए काम कर सकते हैं। राजनाथ ने कहा कि बॉर्डर सुरक्षा और देश की आंतरिक सुरक्षा के बीच का फर्क खत्म होता जा रहा है। अब हाईब्रिड वॉरफेयर की मदद से शांतिकाल में भी देश के अहम इन्फ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। इसलिए हमें तैयार रहने

की जरूरत है। सिंह ने कहा, शांति का वट वृक्ष केवल शक्ति की जड़ों पर ही खड़ा हो सकता है। भारत ने अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत की है।

आतंकवाद, साइबर अपराध भारत के लिए चुनौती

राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद, साइबर अपराध, मानवीय संकट और जलवायु परिवर्तन से होने वाली आपदाएं भारत के लिए बड़ी चुनौती हैं, जो सीमाओं से परे जाकर दुनिया को प्रभावित कर रही हैं। उन्होंने पहल के जरिए वैश्विक सहयोग और सुरक्षा साझेदारी को मजबूत करने की बात कही। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांच 'स' के सिद्धांत- सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि को भारत की अंतरराष्ट्रीय नीति का आधार बताया। राजनाथ सिंह ने कहा कि एक बड़ा देश होने के नाते भारत हमेशा शांति का समर्थक रहा है। हमारे लिए देश की सुरक्षा और शांति एक ही हैं। भारत के एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के नजरिए को कई देश समझते हैं। एयरो इंडिया में आए कई देशों के साथियों की मौजूदगी इस बात को दर्शाती है।

● मिर्जापुर को मीरपुर, सलामतपुर को श्रीरामपुर...

एमपी में उर्दू शब्द वाले 56 गांवों के बदले जाएंगे नाम

भोपाल। मध्य प्रदेश के देवास जिले के 54 गांवों के नाम बदलने की तैयारी है। यह मांग बीजेपी नेताओं ने की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस पर सहमति जताई है। नाम बदलने की वजह इन गांवों के उर्दू नाम हैं। सरकार का कहना है कि यह भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना के लिए जरूरी है। यह खुलासा सोनकच्छ में लाडली बहना योजना के कार्यक्रम में हुआ। देवास जिले में 54 गांवों के नाम बदलने की चर्चा जोरों पर है। ये नाम ज़्यादातर उर्दू मूल के हैं। बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से इन नामों को बदलने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से यह योजना सरकार के विचाराधीन है और जल्द ही इन गांवों के नए नाम लागू कर दिए जायेंगे। यह मामला मध्य प्रदेश में उर्दू नाम वाले गांवों के नाम बदलने के चल रहे विवाद का हिस्सा है। देवास बीजेपी जिला अध्यक्ष रायसिंह सेंधव ने 54 गांवों के नाम बदलने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि ऐसा करना भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना की दिशा में एक अहम कदम होगा। मुख्यमंत्री ने इस मांग पर तुरंत सहमति जताई। उन्होंने कहा कि लंबे समय से उर्दू शब्द वाले गांव के नाम बदलने की योजना सरकार के सामने प्रस्तावित है। इन गांवों के नाम जल्द बदल दिए जाएंगे। प्रस्तावित नाम परिवर्तनों में मुरादपुर को मुरलीपुरा, हैदरपुर को हीरापुर का प्रस्ताव है।

एमपी में ट्रक-ट्रैवलर व कार टकराई, 7 की मौत

● टायर फटने से सड़क की दूसरी साइड घुसा ट्रक
● ट्रैवलर में हैदराबाद के कुल नौ कुंभयात्री थे सवार

जबलपुर (एजेंसी)। कुंभ स्नान कर प्रयागराज से लौट रहे हैदराबाद के 7 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। जबलपुर में मंगलवार सुबह करीब 9 बजे उनकी ट्रैवलर को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। ट्रक और सड़क की रेलिंग के बीच फंसी ट्रैवलर बुरी तरह पिचक गई। इसमें 9 लोग सवार थे। ट्रैवलर सवार सभी लोग अंदर बुरी तरह फंस गए थे, जिन्हें पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला। दो गंभीर रूप से घायल हैं। इस हादसे के बाद सामने से आ रही एक कार ट्रैवलर और ट्रक से टकरा गई। हालांकि, कार सवार सभी लोग एयरबैग खुलने से सुरक्षित हैं। हादसा नागपुर-प्रयागराज नेशनल हाईवे पर जबलपुर से 50 किलोमीटर दूर मोहला बरगी गांव के पास पुल पर हुआ। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। जाम के हालात बने तो पुलिस ने वाहनों को दूसरे रास्ते से निकाला। पुलिस ने बताया कि ट्रक

जबलपुर से पुट्टी लेकर कटनी की ओर जा रहा था। मोहला बरगी के पास ट्रक का टायर फट गया। अनियंत्रित होकर वह सड़क की दूसरी साइड पहुंच गया और प्रयागराज से लौट रही ट्रैवलर को टक्कर मार दी। ट्रैवलर सवार सभी 9 लोग तेलंगाना के रहने वाले हैं। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर इंदौर सहित प्रदेश के बीएड कॉलेजों की जांच शुरू, EOW ने मांगी जानकारी

दैनिक सदभावना पाती की शिकायत पर मध्य प्रदेश आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो ने लिया संज्ञान

पूनम शर्मा

भोपाल/इंदौर। मध्य प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। नर्सिंग कॉलेजों की जांच अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अब बीएड कॉलेजों में फर्जीवाड़े का मामला सामने आ गया है। इन कॉलेजों में संस्थागत अनियमितताओं के साथ-साथ नॉन-अटेंडिंग शिक्षक और छात्रों का चौंकाने वाला सच सामने आया है। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों के बाद आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो (EOW) ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और प्रदेश की विभिन्न यूनिवर्सिटियों से पूरी जानकारी तलब की है।

फर्जी शिक्षक तैयार करने की फैक्ट्री!

शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले शिक्षक यदि खुद फर्जी डिग्रीधारी होंगे, तो देश की शिक्षा प्रणाली का क्या होगा? मध्य प्रदेश में बीएड कॉलेजों की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि कागजों पर तो फैकल्टी मौजूद है, लेकिन ना यहां नियमित कक्षाएं लगती हैं, ना छात्र आते हैं, ना शिक्षक पढ़ाते हैं। सिर्फ परीक्षा के माध्यम से डिग्रियां बांटी जा रही हैं, जिससे शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

'दैनिक सदभावना पाती' ने शिक्षा में हो रहे इस बड़े घोटाले को उजागर करने के लिए लगातार अभियान चलाया। अखबार ने कई रिपोर्ट्स प्रकाशित कर बताया कि कैसे बीएड कॉलेज बिना उपस्थिति के एडमिशन कर केवल फीस वसूलने का काम कर रहे हैं और देश को अशिक्षित शिक्षक उपलब्ध करवा रहे हैं। लेकिन न उच्च शिक्षा विभाग जागा, न देवी अहिल्या विश्वविद्यालय और न ही अन्य विश्वविद्यालय के जिम्मेदार अधिकारियों ने संज्ञान लिया।

अब होगी सख्त कार्रवाई

अब जब ये अनियमितताएं अपराध का रूप ले चुकी हैं, तो 'दैनिक सदभावना पाती' की शिकायत पर EOW ने संज्ञान लिया और जांच शुरू कर दी। प्रदेशभर की यूनिवर्सिटियों से इस घोटाले से जुड़ी जानकारी मांगी गई है। यह जांच फर्जी बीएड कॉलेजों के पूरे नेटवर्क को उजागर करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। अब देखना होगा कि क्या सरकार इस शिक्षा माफिया पर सख्त कार्रवाई करती है या फिर ये मामला भी लंबित फाइलों में दबकर रह जाएगा।

किस तरह से हुआ ये फर्जीवाड़ा ? और जांच की दिशा क्या होगी ? कौन है सबसे बड़ा शिक्षा माफिया ? ऐसे अनेकों सवालों का जवाब जानने के लिए आगे की कड़ियों को अवश्य पढ़िए।

मधुमक्खी ने मारा डंक, तबीयत बिगड़ी फिर हुई मौत

शिवपुरी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से ऐसा ही एक मामला सामने आया है। जहां मधुमक्खी के काटने पर एक महिला की मौत हो गई। रविवार की रात महिला को परिजन मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे थे। लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोसित कर दिया। महिला की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर उपचार में लापरवाही के आरोप लगाया।महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा करना शुरू कर दिया। जिसके बाद मौके कर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराने के बात कही। लेकिन परिजन पोस्टमार्टम कराने को राजी नहीं हुए। इसके बाद परिजन महिला के शव को गांव वापस ले गए।जानकारी के अनुसार, भौंती थाना क्षेत्र के मनपुरा रामनगर 48 वर्षीय रामकुंवर लोधी पत्नी रामकृष्ण लोधी रविवार की शाम 7~30 बजे अपने परिवार के साथ खाना खा रही थी। इसी दौरान वर्तन से पानी पीते वक्त उसे एक बड़ी मधुमक्खी ने होंट पर काट लिया था। कुछ देर बाद महिला को चक्कर आने लगे थे। परिजन महिला को पहले मनपुरा के स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे थे। यहां से मेडिकल कॉलेज रैफर कर दिया गया था। लेकिन मेडिकल कॉलेज में उसकी मौत हो गई।

बर्ड फ्लू की दस्तक: मटन-चिकन की दुकानें सील, दहशत में लोग

छिंदवाड़ा। शहर में बर्ड फ्लू की आशंका के चलते प्रशासन ने कई सख्त कदम उठाए हैं। कुछ स्थानों पर बर्ड फ्लू के ॥5ह1 वायरस की पुष्टि होने पर प्रशासन द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए इन क्षेत्रों में अंडे और मुर्गे की बिक्री पर एक महीने के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। राज टॉकीज क्षेत्र में मटन-चिकन मार्केट को सील कर दिया गया है। इस एरिया में 30 दिन तक चिकन-मटन और अंडों की बिक्री को बंद कर दिया गया है। मंगलवार सुबह बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी यहां पहुंचे और एरिया सील किया।साथ ही छिंदवाड़ा शहर के वार्ड नंबर 31, 30, 28, 29, 41, 6, 8, 7, 26, 27, 43 जो संक्रमित क्षेत्र वार्ड ठ्श 30, मटन मार्केट एरिया से 1 किलोमीटर के दायरे में है, इसे संक्रमित क्षेत्र घोषित किया गया है । इन क्षेत्रों की समस्त मटन / चिकन / अंडे की दुकानों को आगामी 30 दिन के लिए बंद रखा जाएगा। मटन मार्केट वाले वार्ड के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले वार्डों को सर्विलांस पर रखा है, जिनमें स्थित पोल्ट्री फार्म, दुकानों की सतत निगरानी की जाएगी।

मोबाइल पर ऐप डाउनलोड कर खाते से उड़ाया दो लाख रुपए, खुद को बताया था बैंक कर्मचारी

जबलपुर। पुलिस प्रशासन और बैंक प्रंबधन की ओर से जागरुकता अभियान के बाद भी साइबर क्राइम के मामले कम नहीं हो रहे है। जागरुकता अभियान के बाद भी लोग ठगों के झांसे में आकर धोखाधड़ी के शिकार हो रहे है। ताजा मामला मोबाइल पर ऐप डाउनलोड करवा कर दो लाख रुपए ठगी का है। ठग ने खुद को बैंक कर्मचारी बताया था।दरअसल क्रेडिट कार्ड में एक्टिव सर्विस बंद करने का झांसा देकर ऐप डाउनलोड करवाया था। मोबाइल पर ऐप डाउनलोड करवा कर खाते से 2 लाख रुपये उड़ा लिया। क्रेडिट कार्ड में एक्टिव सर्विस के बदले हर महीने ढाई हजार रुपए कटने की बात कहकर झांसे में लिया था। ऐप डाउनलोड होते ही ठग ने अकाउंट से दो लाख रुपए गायब कर दिया। मोबाइल पर एक लिंक भेज कर ऐप डाउनलोड करवाया था। ऐप डाउनलोड करवाने वाले ठग ने खुद को बैंक का कर्मचारी बताया था। साइबर ठगी के शिकार शख्स ने मामले की थाने में शिकायत की है। लार्डगंज थाना पुलिस ने मामला कायम कर जांच शुरू कर दी है।

बीच सड़क पर दो महिलाओं ने युवक की चप्पल और लात-घूंसों से की पिटाई

मुरैना। बीच सड़क पर घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। जिसका वीडियो भी सामने आया है जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दो महिलाएं एक युवक की चप्पल व लात घूंसो से जमकर मारपीट करते हुए नजर आ रही हैं। वहीं सड़क पर लोगों की भीड़ तमाशबीन बनी रही।मामला जिले के कैलारस थाना क्षेत्र का है। जहां अस्पताल के पास एमएस रोड पर दो महिलाओं ने एक युवक की चप्पल और लात-घूंसों से जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान सड़क पर लोगों की भीड़ तमाशबीन बनी रही, लेकिन इनमें में किसी ने भी बीच-बचाव करने की कोशिश नहीं की। इस पूरी घटना का भीड़ में से किसी राहगीर ने वीडियो बना लिया। जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दो महिलाएं युवक के बाल पकड़कर उसकी पिटाई कर रही हैं। वहीं, युवक भी वीडियो में महिलाओं से अभद्रता करते और गाली-गलौज करते नजर आ रहा है। हालांकि, महिलाओं ने युवक की पिटाई क्यों की इसकी वजह अब तक सामने नहीं आई है। वहीं दोनों पक्ष कैलारस थाना पहुंचे, लेकिन किसी ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई।

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, डीआरडीओ से सलाह लेने के निर्देश

ग्वालियर। हाईकोर्ट में शहर में फैली गंदगी और कचरा निस्तारण से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद केंद्र सरकार को इंदौर मॉडल अपनाने के साथ डीआरडीओ से सलाह लेने के निर्देश दिए है।सरताज सिंह ने शहर में फैली गंदगी और कचरा निस्तारण को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़ी इस याचिका पर सभी पक्षों को सुना और उसके बाद केंद्र सरकार को विशेष निर्देश दिए हैं। कहा है कि शासन इंदौर मॉडल का अध्ययन करें और इसे अपनाना नाम बेहद जरूरी हो गया है। इसके लिए एक विशेष कमेटी बनाई जाए जो इंदौर का दौरा करने के बाद तय करें कि किस तरह उनकी कार्य प्रणाली काम कर रही है। यदि उस कार्यप्रणाली का पालन ग्वालियर में किया जाए तो शहर की तस्वीर और रूप बदल सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार डीआरडीओ से इस मामले में सलाह भी ले। बता दें कि जिला से लेकर निगम प्रशासन के साथ ही प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और भोपाल के अफसर को पक्षकार बनाया है। अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी।

कुंभ में जा रही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है, लोगों के खाने-पीने की व्यवस्था, एंबुलेंस भी तैनात की

भोपाल। मध्यप्रदेश में मोहन कैबिनेट की बैठक में प्रयागराज महाकुंभ 2025 में जा रही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार मामले को लेकर पूरी तरीके से मुस्तैद है। रीवा सीधी मैहर में प्रशासन लोगों को आने-जाने में मदद कर रहा है। लोगों के खाने-पीने और चिकित्सा की भी व्यवस्था की गई, एंबुलेंस को भी तैनात किया गया है। इसके साथ ही सभी अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा और उनके रुकने ठहरने के लिए इंतजाम करने के निर्देश दिए है।संसदीय कार्य मंत्री मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक की जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि- ऐतिहासिक बैठक कैबिनेट की हुई है। मध्यप्रदेश के इतिहास में एक साथ इतनी पॉलिसी जो कि निवेश को आकर्षित करती है। प्रदेश के नौजवानों को लेकर सरकार प्रयास कर रही है। 30 साल के राजनीतिक कैरियर में शायद पहली बार इतनी पॉलिसी एक साथ आई है।प्रयागराज के यात्रियों के लिए भाजपा के सभी कार्यकर्ता मदद करेंगे। जेपी नड्डा के निर्देश के बाद फंसे हुए लोगों को निकाला जाएगा। हमारे कार्यकर्ताओं ने भोजन की व्यवस्था की है कोई ठहरने की व्यवस्था भी कर रहा है। बच्चों के साथ गए लोगों को दूध की व्यवस्था भी रहे हैं। मुख्यमंत्री ने डिप्टी सीएम को जिम्मेदारी सौंपी है। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। दिल्ली की जनता को कैबिनेट में बधाई दी गई है। दिल्ली की जनता ने वापस बता दिया है कि बीजेपी की सरकार पर उन पर भरोसा है।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी को लेकर काम चल रहा है। बाहर का निवेश आए इसके लिए मुख्यमंत्री विदेश गए दिल्ली वाणिज्य कर उद्योग विभाग राजदूतों के साथ बैठक करेगा। बाहर के निदेशक मध्य प्रदेश में आकर इन्वेस्ट कर सके इसके लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव विदेश के सारे राजदूतों के साथ बैठक करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी को लेकर एक समूह का गठन भी किया गया है। दो डिप्टी सीएम और भोपाल के प्रभारी मंत्री को भी शामिल किया गया है। स्थाई विधायक और मेयर भी शामिल हैं।बैठक में बताया गया कि 24 को पीएम मोदी शुभारंभ करेंगे और 25 को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आएंगे। मुख्य उद्देश्य पॉलिसी बनाने का है कि मध्य प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिले, निर्यात को बढ़ावा मिले, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी बनी है। अनुमतियों के अंदर जो समस्या आती है कभी 25 अनुमति होती थी तो उसे काम किया गया है और ऑनलाइन अनुमति दी जाएगी। सभी विभागों को निर्देश दिए हैं इस ऑफ डूइंग के तहत सरकार काम कर रही है। लॉजिस्टिक क्षमता को बढ़ाना, लॉजिस्टिक को कैसे मजबूत किया जाए क्योंकि हमारे पास पोर्ट नहीं है, इसके लिए हमने लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई है।ट्रांसपोर्टेशन में भी पॉलिसी को ध्यान में रखा गया है।

एफआईआर दर्ज करो तुम्हारी कोई नौकरी तो नहीं खाएगा:पूर्व मंत्री इमरती देवी

डबरा। बीजेपी नेत्री व पूर्व मंत्री इमरती देवी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें वह पुलिस को धमकाते हुए नजर आ रही है। इमरती कह रही कि एफआईआर दर्ज करो, तुम्हारी कोई नौकरी तो नहीं खाएगा। इतना ही नहीं पूर्व मंत्री के समर्थक भी धमकाते हुए नजर आ रहे है।मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री व भाजपा नेत्री का पुलिस को धमकाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें वह देहात थाना प्रभारी अनुराग प्रकाश से कहती हुई नजर आ रही है कि स्त्रढ्ढक्रधर्ज करो तुम्हारी कोई नौकरी तो नहीं खा लेगा न.. इमरती देवी के समर्थकों ने भी धमकाते हुए कहा कि एफआईआर नहीं करोगे तो तुम यहां नहीं रह पाओगे।दरअसल, दो दिन पहले बालाजी मंदिर के पुजारी सोनू महाराज से मारपीट की गई थी। सोनू महाराज और उनके सेवक के साथ पड़ोस के परिवार ने मारपीट की थी। इसकी सूचना मिलते ही मंदिर से जुड़े भक्त और हिन्दू संगठन देहात थाना पहुंचे थे। भीड़ ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर

नारेबाजी की और आरोपियों पर मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की। बड़ी संख्या में सभी ने थाना में हनुमान चालीसा पाठ कर पुलिस के प्रति विरोध प्रदर्शन किया था। पुलिस के आरोपियों पर लूट की धारा न बढ़ाने पर जमकर बहस हुई। मामला इतना गंभीर हुआ कि सोनू महाराज समेत 200 लोगों की भीड़ ने कृषि उपज मंडी के सामने जाम लगा दिया। इस दौरान महाराज ने सड़क पर ही खुद पर केरोसिन उड़ेल लिया और आत्महत्या करने की कोशिश की थी। यह देख वहां मौजूद सिटी थाना प्रभारी यशवंत गोयल समेत पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। लोगों ने उनके हाथों से केरोसिन छुड़ाया।

इमरती देवी ने पुलिस प्रशासन को सुनाई थी खरी खोटी- सूचना मिलते ही पूर्व मंत्री इमरती देवी भी मौके पर पहुंची और पुलिस प्रशासन को जमकर खरी-खोटी सुनाई थी। इस मामले को लेकर एक बार फिर इमरती देवी थाने पहुंची थी। जहां पुलिस को धमकाते हुए वीडियो सामने आया है। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने सोनू महाराज और उनके भक्त के बयानों के आधार पर मंदिर के पास रहने वाले सतीश, विक्की और अन्नू गुबरेले पर मामला दर्ज किया था। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई।

जुआरी पति ने अपनी पत्नी को ही जुए में दांव पर लगाया

छतरपुर। सनसनीखेज मामला जहां एक पति ने अपनी पत्नी को ही जुए में दांव पर लगा दिया। हारने के बाद जुआरी पति घर पहुंचा और पत्नी से पैसे मांगे, जब पत्नी ने पैसे देने से इनकार किया तो उसने कहा कि अब तुम मेरी नहीं होज इसके बाद पति और ससुराल वालों ने महिला को नग्न कर रातभर पीटा, इतना ही नहीं उसके प्राइवेट पार्ट पर भी चोट पहुंचाई। न्याय की गुहार लगाने एसपी ऑफिस पहुंची पीड़ित महिला ठीक से चल भी नहीं पा रही थी।यह पूरा मामला छतरपुर जिले के गुलगंज थाना क्षेत्र का है। बौकना गांव के रहने वाला प्रदीप सिंह गौड़ जुए में अपनी पत्नी को हार गया। इसके बाद वह पत्नी के पास पहुंचा और पैसे मांगने लगा जब महिला ने पैसे देने से इनकार किया तो पति ने बुरी तरह पीटा जिसके कारण महिला के गुप्तांग में चोट आई है। पीड़ित महिला घायल अवस्था में एसपी ऑफिस पहुंची और न्याय की गुहार लगी।

पीड़िता ने बताया कि उसका पति प्रदीप सिंह गौड़ जुआ खेलने का आदी है। वह आए दिन वह जुआ खेलने जाता है और घर का कुछ न कुछ सामान हार जाता है। इस बार मेरे पति ने जुए के फड़ पर मुझे ही दांव पर लगा दिया और वह हार भी गया। मेरे पति ने कहा कि अगर तुम्हे मेरे साथ रहना है, तो पैसे देने होंगे। जब मैंने पैसे देने से मना किया तो मेरे ससुर और ससुराल पक्ष के कुछ लोगों ने नग्न कर रात भर पीटा, जिससे प्राइवेट पार्ट में चोट आई है।पीड़ित महिला जब एसपी ऑफिस पहुंची तो वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। इधर पुलिस ने पीड़िता के आरोप और शिकायती आवेदन को आधार मानकर पति सहित 3 लोगों पर मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया है। इस पूरे मामले को लेकर एडिशनल एसपी विक्रम सिंह ने बताया कि गुलगंज की महिला शिकायत लेकर आई थी, उनका पारिवारिक विवाद था, जिसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है। विवेचना की जा रही है, साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

म.प्र.में ठंड से राहत, दिन-रात में पारा 5 डिग्री बढ़ा

दो दिन तापमान में बढ़ोतरी ; 13 से सर्दी का एक और दौर

भोपाल (नप्र)। इन दिनों मध्यप्रदेश में ठंड से थोड़ी राहत मिली है। रात के बाद पारे में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। गुना में एक ही दिन में पारा 5.4 डिग्री बढ़ गया। रतलाम-सिवनी में 33 डिग्री और मंडला में 33.5 डिग्री रहा। अधिकांश शहरों में पारा 30 डिग्री से ज्यादा ही रहा। ऐसा ही मौसम अगले 2 दिन और बना रहेगा। 13 फरवरी से सर्दी का दूसरा दौर आ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक, मंगलवार को गर्मी का असर देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिक वीएस यादव ने बताया, 8 फरवरी को एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) उत्तर भारत पहुंचा था। इसके असर के कारण प्रदेश में उत्तर से सर्द हवाएं चल रही थी, जो अब लौट गई है। अब राजस्थान के पास एक प्रेरित चक्रवात (इंड्यूस साइसर) बन गया है। इसके कारण हवा का रुख बदल कर दक्षिणी हो गया है। ऐसे में उत्तर से सर्द हवा नहीं आ रही है।

पृथ्वी के सबसे रहस्यमय हिस्से में हो रहा बदलाव

वॉशिंगटन (एजेंसी)। वैज्ञानिकों ने हमारी पृथ्वी के सबसे गहरे छिपे रहस्य के बारे में एक नया खुलासा किया है। वैज्ञानिकों ने हमारे ग्रह के आंतरिक कोर के आकार में परिवर्तन की पहचान की है। पृथ्वी का सबसे भीतरी हिस्सा, जिसे इनर कोर के रूप में जाता है, एक तरल धातु के बाहरी कोर से घिरी हुई है। दशकों से वैज्ञानिकों को संदेह था कि ठोस आंतरिक कोर समय के साथ विकृत हो गया है। अब शोधकर्ताओं ने आंतरिक कोर के आकार में बीते 20 साल में होने वाले परिवर्तनों का पहला सबूत पाया है। शोधकर्ताओं ने अध्ययन के लिए पृथ्वी में आने वाले भूकंप के डेटा का इस्तेमाल किया, जो पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे। अध्ययन के दौरान पाया कि आंतरिक कोर एक समय में पृथ्वी से भी तेज घूमता था, लेकिन 2010 के आसपास ठोस

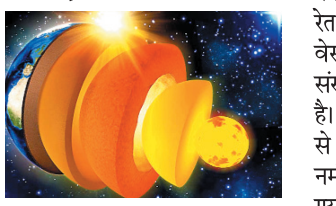

आंतरिक कोर का घूमना धीमा हो गया। यह अब पृथ्वी के बाकी हिस्सों की तुलना में पीछे की ओर घूम रहा है। सोमवार को नेचर जियोसाइंस पत्रिका में प्रकाशित नए अध्ययन में 1991 से 2023 तक जुटाए गए भूकंप के आंकड़ों का उपयोग करते हुए आकलन निकाला गया है। अध्ययन के प्रमुख लेखक डॉ. जॉन विडेल ने कहा कि कोर रोटेशन पर वैज्ञानिकों के पिछले काम ने उन्हें भूकंपीय तरंगों की ऊंचाई में बदलावों की व्याख्या करने में मदद की। पृथ्वी विज्ञान के डीन प्रोफेसर विडेल ने सीएनएन को बताया कि हम उन संकेतों की तुलना कर सकते हैं, जो हमें मिले हैं।

बीजेपी सांसद बोले- अवैध रेत खनन से नर्मदा पर खतरा

संसद में कहा- नदी का मूल स्वरूप बदल रहा ; नेता प्रतिपक्ष बोले- 20 साल से भाजपा की सरकार

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में नदियों से अवैध रेत खनन के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरता रहा है। हालांकि इस बार मप्र की लाइफलाइन कही जाने वाली नर्मदा नदी में अवैध रेत खनन और औद्योगिक ईकाईयों का वेस्ट नर्मदा में मिलने का मामला संसद में बीजेपी के सांसद ने उठाया है। उन्होंने कहा कि, गैरकानूनी तरीके से अत्यधिक रेत खनन के कारण नर्मदा जी पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है।

सांसद चौधरी के संसद पर उठाए इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी पर निशाना साधा हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि, मप्र में 20 साल से बीजेपी की सरकार है, पर किसी ने नर्मदा संरक्षण को गंभीरता से नही लिया। प्रदेश में जो रेत माफिया पनप रहा है, उसे भी बीजेपी के नेताओं और अफसरों का आश्रय हैं।

एमपी के साथ गुजरात की भी जीवनरेखा है नर्मदा नदी- होशंगाबाद से बीजेपी सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान नर्मदा नदी का मुद्दा उठाया। दर्शन सिंह ने सवाल से पहले नर्मदा मैया का जयकारा लगाया और कहा- जीवनदायिनी मां नर्मदा के संरक्षण की

आज अति आवश्यकता है। नर्मदा नदी न केवल मध्य प्रदेश बल्कि गुजरात की जीवन रेखा है।

चौधरी ने कहा- न केवल धार्मिक व आर्थिक दृष्टि से भी मां नर्मदा का संरक्षण अति आवश्यक है बल्कि इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश की अधिकतम नदियां फ्रेश वाटर बॉडी, औद्योगिक प्रदूषण, अति उपभोग व संरक्षण के अभाव में ह्यूमन कंजप्शन के लिए अनफिट होती जा रही हैं।

नर्मदा के संरक्षण की योजना पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएं- होशंगाबाद सांसद ने आगे कहा, गैरकानूनी तरीके से अत्यधिक रेत खनन के कारण नर्मदा जी पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। मां नर्मदा के संरक्षण के लिए मैं जल मंत्रालय से निवेदन करता हूं कि सेंट्रल वाटर कमीशन के संसाधनों का उपयोग करके नर्मदा नदी के संरक्षण की योजना पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई जाए।

इस रिपोर्ट में करंट स्टेटस ऑफ क्वालिटी ऑफ रिवर वॉटर, औद्योगिक क्षेत्र का कितना वेस्ट नर्मदा में डिस्चार्ज किया जा रहे है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इंडस्ट्री जैसे सख्ती से उपाय किए जाएं जिससे नर्मदा का पानी फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन हो।

उसमें लगने वाली राशि व कर में सरकार को प्राइवेट उद्योगों की भूमिका तय करनी चाहिए।

साबरमती की तर्ज पर रिवर फ्रंट बनाया जाए

सांसद चौधरी ने कहा- साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर नर्मदा पुरम में विश्व स्तरीय नर्मदा रिवर फ्रंट का विकास किया जाए। इस कार्य के लिए एक सीरियस पर्पज पर काम करने की जरूरत है। नर्मदा नदी विकास प्राधिकरण डेट बढ़ाकर इन संरक्षण के उपाय को करने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल मेकेनिज्म बनाया जाए।

सांसद ने कहा- गोस्वामी तुलसीदास जी ने नर्मदा नदी के बारे में कहा है- सिव प्रिय मैकल सैल सुता सी, सकल सिद्धि सुख संपति रासी।। अर्थात- नर्मदा एकमात्र नदी है जिसकी परिक्रमा होती है जो न के मध्य को हर रही है इसलिए मां नर्मदा का लोग और नर्मदा पद की स्थापना करते हुए इसको संरक्षित किया जाए।

नेता प्रतिपक्ष बोले- 20 साल से भाजपा की सरकार है, किसी ने गंभीरता से नहीं लिया

होशंगाबाद सांसद के संसद में नर्मदा नदी प्रदूषण के उठाए मुद्दे के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि, मप्र में 20 साल से भाजपा की सरकार है, पर किसी ने नर्मदा संरक्षण को गंभीरता से नही लिया। प्रदेश में जो रेत माफिया पनप रहा है, उसे भी बीजेपी के नेताओं और अफसरों का प्रश्रय है।

दैनिक
सद्भावना पाती
...प्राणियों में सद्भावना हो...

स्कूली बच्चों को सुरक्षित इंटरनेट के संबंध में दी गई जानकारी

इंदौर। भारत सरकार के निर्देशानुसार फरवरी माह के द्वितीय मंगलवार पर 11 फरवरी को %सुरक्षित इंटरनेट दिवस% मनाया गया। इस वर्ष भारत सरकार द्वारा सुरक्षित इंटरनेट दिवस के अवसर पर ÷टुगेदर फॉर द बेटर इंटरनेट÷ थीम पर इस दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर इंदौर में शासकीय मालव कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों में सुरक्षित इंटरनेट उपयोग के संबंध में जागरूकता लाना है। इस आयोजन में एनआईसी के निदेशक शैलेंद्र कुमार नाहर, डीआईओ श्रीमती शीतल पाठक, आरसीबीसी लीड ट्रेनर अतुल पांडे ने उपरोक्त विषय पर छात्राओं से परिचर्चा कर सुरक्षित इंटरनेट एवं इससे जुड़ी अन्य जिज्ञासाओं का समाधान किया। इस अवसर पर स्कूल की प्राचार्य एवं अन्य शिक्षकगण उपस्थित रहे।

महापौर द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं पूर्व मंत्री लक्ष्मण सिंह गौड़ की प्रतिमा पर माल्यार्पण

इंदौर। 11 फरवरी मंगलवार प्रातःकाल, महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के अवसर पर बिलावली झोन उद्यान में स्थापित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर अनेक गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों एवं वरिष्ठो द्वारा प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके साथ ही माननीय महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्री लक्ष्मण सिंह गौड़ जी की पुण्यतिथि के अवसर पर महू नाका चौराहे पर स्थापित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। महापौर भार्गव के साथ पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे, भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, विधायक मधु वर्मा, श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़, महापौर परिषद सदस्य अभिषेक शर्मा, निरंजन सिंह चौहान, अश्विनी शुक्ल, पार्षद श्रीमती सुनीता सुनील हडिया, प्रशांत बडवे, श्रीमती कंचन गिद्वानी सहित अन्य वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों ने भी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर उपस्थित सभी गणमान्य जनों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों एवं सिद्धांतों को आत्मसात करने का संकल्प लिया और उनके एकात्म मानववाद के दर्शन को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया।

आयुक्त द्वारा शासकीय स्कूलों का निरीक्षण, ग्रेटर कैलाश आदर्श रोड का किया निरीक्षण

इंदौर। आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा द्वारा शहर के विभिन्न शासकीय स्कूलों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने स्वच्छता की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर आयुक्त अभिलाष मिश्रा, कार्यपालन यंत्री लक्ष्मीकांत वाजपेई, जोनल अधिकारी शैलेंद्र मिश्रा एवं अन्य विभाग अधिकारी उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान खजराना रिंग रोड स्थित शासकीय स्कूल एवं ग्रेटर कैलाश आदर्श रोड का विशेष रूप से भ्रमण किया गया। आयुक्त श्री वर्मा ने विद्यालय परिसरों में पर्याप्त पेयजल, स्वच्छ शौचालयों और सफाई व्यवस्था की स्थिति का मूल्यांकन किया। उन्होंने अधिकारियों एवं विद्यालय प्रबंधन को स्वच्छ सर्वेक्षण की गाइडलाइन के अनुरूप समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आयुक्त श्री वर्मा ने कहा कि स्वच्छता केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि आदत होनी चाहिए। उन्होंने विद्यालयों में स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने पर भी जोर दिया, जिससे छात्र-छात्राएं स्वच्छता के प्रति जागरूक बनें और इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं।

सांवेर में 96 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 6 हजार से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की सौगात

इंदौर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प को साकार करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रत्येक गरीब एवं बेघर परिवार को पक्का मकान प्रदान किए जाने के लिए तेजी से प्रयास किये जा रहे हैं। इन प्रयासों के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत इंदौर जिले की सांवेर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2015 से वर्ष 2024-25 तक 96 करोड़ 09 लाख रुपये की लागत से कुल 6152 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 2446 पात्र हितग्राही परिवारों को आवास प्रदान किए जा चुके हैं। योजना अंतर्गत जनपद पंचायत सांवेर में वर्ष 2015 से वर्ष 2024-25 तक 49 करोड़ 88 लाख रुपये की लागत से कुल 3563 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 1203 पात्र हितग्राही परिवारों को आवास प्रदान किए जा चुके हैं। जनपद पंचायत इंदौर में वर्ष 2015 से वर्ष 2024-25 तक 23 करोड़ 46 लाख रुपये की लागत से कुल 1698 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 752 पात्र हितग्राही परिवारों को आवास प्रदान किए जा चुके हैं। इसी प्रकार नगर परिषद, सांवेर में वर्ष 2015 से वर्ष 2024-25 तक 12 करोड़ 75 लाख रुपये की लागत से कुल 491 पात्र हितग्राही परिवारों को आवास प्रदान किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत नगर परिषद सांवेर में 10 करोड़ रुपये की लागत से 400 पात्र हितग्राही परिवारों को आवास प्रदान किए जाना प्रस्तावित है, जिसमें वर्तमान में 198 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट द्वारा शेष 2760 आवासों के संबंध में हितग्राहियों का सर्वे किया जाकर पात्र हितग्राही परिवारों की सूची बनाए जाने एवं आवास प्रदान किए जाने संबंधी निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। इस योजना के तहत कच्चे मकानों में रहने वाले या बिना छत वाले परिवार को पक्के मकान बनवाने के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाती है, जिसमें सभी आवश्यक सुविधा उपलब्ध होती है।

आपसी विवाद में एक युवक का कान काटा, मामला दर्ज

इंदौर। राऊ थाना क्षेत्र में आपसी कहासुनी के बाद दो युवकों में जमकर मारपीट हुई इस दौरान एक युवक में दूसरे युवक का कान चबा डाला जिसमें युवक का कान कट कर अलग हो गया फिलहाल दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है।दरअसल राऊ थाना क्षेत्र के आईपीएस कॉलेज के पास आपसी कहा सुनी में शुभम और मनोज नामक युवक के बीच में विवाद हो गया था विवाद इतना बड़ा की दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई इस दौरान मनोज नामक युवक ने शुभम का कान अपने मुंह से चबा डाला जिसमें शुभम का कान कट कर अलग हो गया इस दौरान मनोज पर शुभम ने बियर की बोतल से सर पर हमला कर दिया जिसमें वह भी घायल हुआ है दर्शन शुभम और मनोज के बीच में रास्ते पर चलने को लेकर मामूली कहा सुनी हुई थी जिसके बाद यह विवाद उपजा था फिलहाल दोनों पक्षों की शिकायत पर एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।

कर्ज से परेशान युवक ने की आत्महत्या

इंदौर। शहर के एमआईजी थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां कर्ज से परेशान होकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।एमआईजी थाना क्षेत्र के नेहरू नगर का है। यहां रहने वाले योगेश नामक युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मकान मालिक ने जब यह देखा, तो तुरंत पुलिस को सूचना दी।

चोइथराम मंडी में आज धरना-प्रदर्शन

इंदौर। चोइथराम मंडी में कचरा, गंदगी और वाहनों के गुत्थम गुत्था होने की घटनाएं तो रोज की कहानी है। बाहर एवं लोकल व्यापारी और किसान दोनों ही यहां असुरक्षा का भाव देख रहे हैं। कई बार व्यापारियों के साथ लूटपाट एवं किसान के साथ भी मारपीट की घटनाएं रुक नहीं रही। मंडी प्रबंधन की ओर से शहर की चोइथराम, छावनी और लक्ष्मीबाई अनाज मंडी तीनों स्थानों पर सैकड़ों सुरक्षाकर्मियों की तैनाती का दावा किया जाता है। तीन अलग-अलग शिफ्ट में सुरक्षाकर्मी यहां तैनात बताए जाते हैं, किसान संगठनों का कहना है कि सिर्फ कागजों में ही सुरक्षाकर्मी मंडी प्रबंधन ने लगा रखे हैं। मौके पर सुरक्षाकर्मी नहीं रहते रात में तो सिर्फ सीटियों कि आवाज ही आती हैं। जब भी कोई घटना होती है तो मौके पर सुरक्षाकर्मी नहीं होते। यहां तक की वाहनों के जाम लगे के बाद मंडी प्रबंधन के कर्मचारी यहां घंटों बाद ही पहुंचते हैं। किसान सेना के बबलू जाधव ने बताया कि 10 फरवरी की रात में किसान के साथ चाकूबाजी की घटना के बाद भी मंडी प्रबंधन का रवैया लचर रहा। अब किसानों के साथ मिलकर कल चोइथराम मंडी में प्रदर्शन किया जाएगा और किसानों की सुरक्षा के लिए कलेक्टर एवं कृषि मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। किसानों के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री इस प्रतिनिधिमंडल मामले को गंभीरता से रखेगा।मंडी में सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, व्यापारी और किसानों की हजारों की संख्या में रोज आवाजाही होती है । कुछ असामाजिक तत्व यहां सक्रिय बने हुए हैं जिनको बाहर निकालने की कवायद भी जारी है। सुरक्षा कर्मियों का ऑडिट भी किया जा चुका है, और ज्यादा सख्त इंतजाम किए जाएंगे।

पीथमपुर में शव सत्याग्रह : यूनियन कार्बाइड कचरे को लेकर अनोखा प्रदर्शन आज

धार। भोपाल गैस त्रासदी के जहरीले कचरे को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के शिवाजी चौक पर शव सत्याग्रह किया। योगाचार्य डॉ. प्रदीप दुबे 15 मिनट तक शव की मुद्रा में लेटे रहे। वहीं आज 12 फरवरी को दोपहर 12 बजकर 12 मिनट, 12 सेकंड का विरोध किया जाएगा।राजधानी भोपाल के यूनियन कार्बाइड के रासायनिक कचरे को लेकर धार जिले के पीथमपुर क्षेत्र के लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक ओर प्रशासन जन समस्या निदान शिविर लगाकर धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा और पुलिस अधीक्षक सहित प्रशासनिक अमला रासायनिक कचरे के संबंध में लोगों के सवालों का जवाब दे रहे हैं, उनकी समस्याओं का निदान कर रहे हैं, वहीं इसी कचरे को लेकर पीथमपुर बचाओ समिति सहित कई अन्य संगठन भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।यूनियन कार्बाइड कचरे को लेकर मशाल यात्रा निकाली जा रही है। वहीं कल सोमवार की शाम एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला।

सेटलमेंट में लगे लोकायुक्त के दो डीएसपी हटाए गए, जांच शुरू

इंदौर। आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकायुक्त के सख्त निर्देश के बावजूद कार्रवाई करने के बजाय सेटलमेंट में लगे लोकायुक्त एसपी कार्यालय इंदौर के दो डीएसपी हटा दिए गए हैं। दोनों अफसरों के खिलाफ जांच शुरू हो गई है और उनकी लोकायुक्त संगठन से वापसी भी तय है।स्टेट जीएसटी में पदस्थ एक महिला अफसर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकायुक्त को शिकायत हुई थी। मुख्यालय के निर्देश के बाद इसकी जांच लोकायुक्त एसपी इंदौर कार्यालय में पदस्थ डीएसपी अनिरुद्ध वाडिया और आरडी मिश्रा कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक दोनों अफसरों ने शिकायत सही पाए जाने के बाद भी कार्रवाई करने के बजाय उक्त अफसर को तलब कर मामला निपटाने के लिए सेटलमेंट की बात कही। महिला अफसर ने इन दोनों अधिकारियों से हुई पूरी बातचीत की ऑडियो क्लिपिंग लोकायुक्त को पेश कर दी, जिसमें कई ऐसी बातें थीं, जिससे यह स्पष्ट हो रहा था कि बजाय कार्रवाई के दोनों अफसर सेटलमेंट से इस मामले को निपटाना चाहते थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए लोकायुक्त के निर्देश पर डीजी लोकायुक्त जयदीप प्रसाद ने दोनों अफसरों को तत्काल इंदौर कार्यालय से हटकर भोपाल मुख्यालय पर अटैच कर दिया। शनिवार को ही दोनों को इंदौर से कार्यमुक्त भी कर दिया गया। इनके खिलाफ जांच भी शुरू कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक इन दोनों अफसरों द्वारा जांच के नाम पर अलग-अलग विभागों के कुछ अफसरों को प्रताड़ित करने के मामले पिछले दिनों सामने आए थे।

आपके पार्सल में ड्रग्स है खाकी को भी नहीं छोड़ रहे साइबर अपराधी

इंदौर। साइबर अपराधी अब पुलिस को भी नहीं छोड़ रहे है। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने आया है। जहां असली पुलिसकर्मी को नकली पुलिसकर्मी ने वीडियो कॉल आया। अपराधी ने कहा कि आपके पार्सल से ड्रग्स जब्त हुआ है, आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। जब असली पुलिस ने अपनी वर्दी दिखाई तो साइबर अपराधी ने आनन-फानन में कॉल काट दिया। इसका वीडियो भी सामने आया है।इंदौर ग्रामीण डीएसपी उमाकांत चौधरी के पास एक फर्जी वीडियो कॉल आया। यह कॉल साइबर अपराधी ने नकली पुलिसकर्मी बनकर किया था। कॉलर ने कहा कि कॉल मत काटनाज आपके पार्सल से ड्रग्स जब्त हुआ है, आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। जब डीएसपी उमाकांत ने चेहरे के साथ अपनी वर्दी दिखाई तो साइबर अपराधी ने खुद ही कॉल काट दिया।वहीं डीएसपी उमाकांत चौधरी ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधी पुलिस को भी नहीं छोड़ रहे है तो आप क्या है ? इस तरीके से ये आपको भी कॉल वीडियो कॉल करेंगे, आपको डर दिखाकर डिजिटल अरेस्ट करेंगे और फिर पैसा वसूलेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह से कोई डिजिटल अरेस्ट नहीं होता है, इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है।आपके पास भी इस तरह से कोई कॉल या डिजिटल अरेस्ट की धमकी देने वालों का फोन आता है, तो तुरंत सायबर सेल से संपर्क करें। आपको किसी तरह की साइबर अपराध की जानकारी मिलती है तो उसकी शिकायत अपने नजदीकी पुलिस थाने में या www.cybercrime.gov.in Øæ cyber crime help line (toll free) नंबर 1930 पर कॉल करें।

बिजली की दरें बढ़ाने की याचिका पर नौटंकी, उपभोक्ताओं ने दायर की आपत्ति

इंदौर। बिजली कंपनियों ने हर साल की तरह इस बार भी विद्युत नियामक आयोग के समक्ष याचिकाएं दायर कर बिजली की दरों में वृद्धि की अनुमति मांगी है। इन कंपनियों ने अपनी याचिकाओं में 4 हजार करोड़ रुपए से अधिक का घाटा बताया है, जिसमें इंदौर की पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी भी शामिल है, जिसने 1618 करोड़ के घाटे का हवाला देकर साढ़े 7 फीसदी तक बिजली महंगी करने के प्रस्ताव सौंपे हैं, जिस पर आयोग आज सुनवाई की नौटंकी कर रहा है और वैसे भी गिनती के उपभोक्ताओं ने आपत्तियां प्रस्तुत की हैं।लाखों की संख्या में घरेलू, व्यवसायिक और अन्य श्रेणी के उपभोक्ता इंदौरी कम्पनी के ही हैं। मगर हर साल जो दावे-आपत्तियां नियामक आयोग द्वारा बुलवाई जाती है उसमें गिनती के ही उपभोक्ताओं और उनमें भी औद्योगिक संगठनों, एनजीओ और कुछ चुनिंदा विशेषज्ञों द्वारा ही दावे-आपत्तियां प्रस्तुत करते हुए बिजली कम्पनी की याचिकाओं का विरोध किया जाता है। मगर आम उपभोक्ता, जिसे हर साल बिजली की बढ़ी हुई कीमतों का भार उठाना पड़ता है, उसकी ओर से इसलिए भी आपत्तियां प्रस्तुत नहीं होती क्योंकि जानकारी का भी अभाव रहता है। पिछले दिनों मध्यप्रदेश पॉवर जनरेशन कंपनी के साथ प्रदेश की तीनों वितरण कंपनियों ने बिजली की दरें बढ़ाने के संबंध में आयोग के समक्ष याचिका दायर की, जिसमें 4 हजार करोड़ से अधिक का घाटा बताते हुए 7.52 फीसदी दरें बढ़ाने के प्रस्ताव सौंपे, जिस पर आयोग की ओर से दावे-आपत्तियां आमंत्रित की गई, ताकि उनकी विधिवत सुनवाई की जा सके। इंदौर की बिजली कम्पनी की याचिका पर आई आपत्तियों की सुनवाई आज 11 फरवरी को हो रही है। वहीं पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों की आपत्तियों की सुनवाई 13 फरवरी को और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण की आपत्तियों की सुनवाई 14 फरवरी को होगी। हालांकि जो गिनती की आपत्तियां आई हैं उनमें भी बिजली कम्पनी द्वारा बताए गए घाटे को गलत ठहराया गया है, क्योंकि पारेषण क्षति के साथ-साथ बिजली की चोरी भी बड़े पैमाने पर अभी भी होती है, जिसके चलते बिजली कंपनियों को घाटा बताना पड़ता है और इसका खामियाजा ईमानदार उपभोक्ता भरते हैं। इन बिजली कंपनियों ने आगामी वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 58744 करोड़ रुपए के राजस्व की जरूरत बताई है और वर्तमान बिजली की दरों के मुताबिक उसकी आय 54636 करोड़ रुपए ही होती है। लिहाजा जो अंतर है, उसे पाटने के लिए बिजली की दरें बढ़वाई जाएंगी। आज सुनवाई की नौटंकी करने के बाद नियामक आयोग दर वृद्धि की अनुमति दे देगा और संभवत~ मार्च या अप्रैल से उपभोक्ताओं को अधिक दरों पर बिजली बिल भरना पड़ेंगे। इंदौरी कम्पनी ने अपना घाटा 168 करोड़ का याचिका में बताया है।

चोरी की वारदातों से मचा हड़कंप, 100 कैमरों की जांच के बाद पकड़े गए चोर

इंदौर। एरोड्रम थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने तीन शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 10 लाख रुपए से अधिक मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आरोपी अपने महंगे शौक पूरा करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम देते थे।पिछले कुछ दिनों में एरोड्रम थाना क्षेत्र के नरीमन सिटी, छोटा बांगड़दा, कावेरी नगर और स्कीम नंबर 51 में लगातार चोरी की घटनाएं सामने आई थी। पुलिस ने इन वारदातों की जांच के लिए घटनास्थलों के आसपास के 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। इन फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति नजर आया, जो चलते समय लंगड़ा रहा था। पुलिस ने इस खास पहचान पर ध्यान केंद्रित किया और मुखबिरों को सतर्क कर दिया। इसी कड़ी में एक संदिग्ध की पहचान संदीप उर्फ संजू पिता गंगाराम चौहान, निवासी हातोद के रूप में हुई।

मुख्य आरोपी सहित तीन गिरफ्तार

संदीप को हिरासत में लेकर जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने चोरी की घटनाओं में शामिल होने की बात कबूल ली। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने दो अन्य आरोपियों भूपेंद्र उर्फ भूरा निवासी छतरीपुरा और सुनील पिता देवराम जमरा को भी गिरफ्तार किया। पूछताछ में इन तीनों ने बताया कि वे अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे।डीसीपी विनोद कुमार मीणा ने बताया की मुख्य आरोपी संदीप उर्फ संजू के खिलाफ पहले से ही 26 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन चोरियों में उसका ही मास्टरमाइंड होना सामने आया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों से करीब 10 लाख रुपए से अधिक के सोने-चांदी के जेवरात और अन्य चोरी का सामान बरामद किया है। डीसीपी ने बताया कि इन आरोपियों की गिरफ्तारी से क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगेगी।

स्कूलों की मनमानी पर शिकंजा कसने की तैयारी, शिकायतों के बाद लिया गया निर्णय

इंदौर। जिले में निजी स्कूल संचालकों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने सख्त कदम उठाए हैं। उन्होंने एक नया आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अब कोई भी निजी स्कूल छात्रों को कॉपी, किताबें या स्कूल ड्रेस खरीदने के लिए किसी विशेष दुकान से सामान लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकेगा।इस नए आदेश के तहत सभी निजी स्कूलों को कम से कम तीन दुकानों की सूची जारी करनी होगी, जहां से अभिभावक अपनी सुविधा और बजट के अनुसार किताबें, कॉपियां और स्कूल ड्रेस खरीद सकेंगे। इस सूची को कलेक्टर कार्यालय द्वारा अधिकृत किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी स्कूल एकलव्य नीति अपनाकर अभिभावकों पर दबाव न बना सके।कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि प्रशासन को लगातार यह शिकायतें मिल रही थीं कि निजी स्कूल संचालक कुछ निश्चित दुकानों से ही कॉपी-किताबें और ड्रेस खरीदने का दबाव बनाते हैं। इस वजह से अभिभावकों को अधिक कीमत चुकानी पड़ती थी और उन्हें सीमित विकल्पों तक ही सीमित कर दिया जाता था। इस मनमानी को रोकने के लिए, नया शिक्षण सत्र शुरू होने से पहले ही यह आदेश लागू कर दिया गया है।

अभिभावकों को मिलेगी राहत

यह आदेश न केवल निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाएगा, बल्कि अभिभावकों को भी आर्थिक और मानसिक रूप से राहत प्रदान करेगा। आदेश लागू होने से अभिभावक अपनी सुविधा और बजट के अनुसार किसी भी दुकान से आवश्यक शैक्षणिक सामग्री खरीद सकते हैं। इसके अलावा, अधिकृत दुकानों की सूची होने से अनावश्यक रूप से महंगी किताबों और ड्रेस की बिक्री पर भी अंकुश लगेगा। कलेक्टर आशीष सिंह का यह कदम शिक्षा प्रणाली में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के तहत 574 ग्रामों में कार्य पूर्ण- 21 ग्राम पंचायतों में बचे हुए कार्य इसी माह के अंत तक होंगे पूरे

समय सीमा में कार्य पूरा नहीं करने वाली निर्माण एजेंसियों के विरुद्ध होगी कार्रवाई

इंदौर। कलेक्टर आशीष सिंह ने निर्देश दिए हैं कि जिले में प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के अंतर्गत ऐसी पंचायतें जिनमें अभी कुछ काम शेष है, उन्हें शीघ्र गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए। योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही और उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिंह ने बचे हुए कार्यों को इसी माह के अंत तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस माह के अंत तक कार्य पूरा नहीं करने वाली निर्माण एजेंसियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिले में हर घर में नल से जल पहुँचाने के लिए चल रही योजना के तहत मात्र 21 ग्रामों में ही काम शेष है। हर घर में नल से जल वाला जिला घोषित करने की तैयारियां अंतिम दौर में है, इसके लिए तेजी से प्रयास जारी है। कलेक्टर आशीष सिंह ने आज यहां जिला पंचायत सभाकक्ष में प्रधानमंत्री जल जीवन

मिशन के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिद्धार्थ जैन, पीएचई के कार्यपालन यंत्री एस.के. उदिया सहित योजना से जुड़े अधिकारी, एसडीएम, अन्य संबंधित अधिकारी-कर्मचारी आदि मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने ऐसी पंचायतें जिनमें अभी कुछ काम शेष है, उन पंचायतों में चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि जिले में 21 पंचायतों में कुछ ही काम बचा है। कलेक्टर सिंह ने निर्देश दिए की शेष पंचायतों में बचे कार्यों को इस माह के अंत तक पूर्ण किया जाए। कार्य को पूर्ण करने के लिए दिन-प्रतिदिन की कार्य योजना बनाई जाए और प्रतिदिन प्रगति की समीक्षा की जाए। कार्यों में गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही तथा उदासीनता बरतने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। हर सप्ताह प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जा रही है। बैठक में जानकारी दी गई कि इंदौर जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 566 गांवों में हर घर में नल से जल पहुंचाने की योजना स्वीकृत की गई है। जिले में पूर्व से शत-प्रतिशत नल कनेक्शन वाले 29 ग्राम है। इस तरह जिले में कुल 595 ग्रामों में हर घर में नल से जल पहुंचाने की योजना है। जिले में अभी तक इसमें से 574 गांवों में नल जल योजना का कार्य पूर्ण हो गया है। उक्त सभी योजनाएं पंचायतों को हस्तांतरित कर दी गई है। शेष 21 ग्रामों में कार्य प्रगति पर है, इन शेष सभी पंचायतों में कार्य अतिशीघ्र पूर्ण कर संबंधित पंचायत को हस्तांतरित करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर आशीष सिंह ने संबंधित पंचायतों के सरपंचों को भी निर्देशित किया है कि वे पूर्ण योजना को शीघ्र हाथ में लेकर बेहतर संचालन सुनिश्चित करें। हर घर में नल से जल पहुंचाएं। इस कार्य में किसी भी तरह के लापरवाही नहीं बरती जाए।

संपादकीय

'फ्री की राजनीति' पर जनता का फैसला, दिल्ली का रुख बदला

दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित नहीं कहे जा सकते। यह चुनाव शुरू से दो-ध्रुवीय था। भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच सीधी टक्कर थी। कांग्रेस ने जरूर दावेदारी की थी, मगर जैसे-जैसे चुनाव की सरगर्मी बढ़ती गई, उसे अहसास होने लगा था कि वह मुकाबले में नहीं है। इसका नतीजा यह हुआ कि उसे शिथिलता ने घेर लिया। भाजपा लंबे समय से आम आदमी पार्टी की कमजोरियों और अनियमितताओं को उजागर करती आ रही थी। इस तरह वह लोगों के मन में सत्ताविरोधी लहर पैदा करने में कामयाब भी हुई। हालांकि तमाम सर्वेक्षणों से यही पता चल रहा था कि दिल्ली की बड़ी आबादी आम आदमी पार्टी सरकार से बहुत नाखुश नहीं थी, मगर उनमें से काफी लोग इस बार बदलाव चाहते थे। आम आदमी पार्टी की साख को सबसे अधिक नुकसान कथित शराब घोटाले की वजह से हुआ।

इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ा था। पार्टी लगातार दलील देती रही कि उसके नेताओं को झूठे आरोप में फंसाया गया है, मगर वह लोगों के गले नहीं उतरी। उन्होंने दागी नेताओं को शिकस्त दी। इन नतीजों से यह भी जाहिर हुआ है कि भाजपा के काम पर लोगों का भरोसा कमजोर नहीं हुआ है।

हालांकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार मुद्दों से अधिक मुफ्त की योजनाओं का शोर सुनाई दिया। आम आदमी पार्टी सरकार पहले से मुफ्त बिजली-पानी और शिक्षा-स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का लाभ लोगों को पहुंचा रही थी। इसे लेकर बहुत सारे लोगों के मन में एक आकर्षण बना हुआ था। फिर सरकार ने चुनाव से ऐन पहले घोषणा कर दी कि वह हर महिला को इक्कीस सौ रुपए हर महीने देगी। इसके लिए पंजीकरण भी शुरू कर दिया। इसके जवाब में भाजपा ने ढाई हजार रुपए हर महीने देने की घोषणा कर दी। फिर यह भी भरोसा दिलाया कि जो योजनाएं पहले से चल रही हैं, अगर उसकी सरकार बनी तो, उन्हें बंद नहीं किया जाएगा।

इस वादे पर लोगों ने भरोसा किया। दूसरे कुछ राज्यों में भी भाजपा महिलाओं के लिए नगद राशि देने की योजनाएं चला रही है। जबकि पहले भाजपा खुद दिल्ली सरकार की मुफ्त की योजनाओं की मुखर आलोचना करती थी, मगर चुनाव आते ही उसने भी आम आदमी पार्टी को उसी के दांव से पटखनी देने का फैसला कर लिया और उसमें उसे कामयाबी भी मिली।

दिल्ली सरकार के पास शासन क्षेत्र सीमित है, उसे केंद्र के साथ तालमेल बिठा कर ही विकास योजनाओं पर आगे कदम बढ़ाना होता है। आम आदमी पार्टी सरकार और केंद्र के बीच शुरू से तनातनी बनी हुई थी, जिसके बीच अपने अधिकारों को लेकर कई बार केजरीवाल सरकार को अदालत तक का दरवाजा खटखटाना पड़ा। उपराज्यपाल से उनके रिश्ते कभी समरस नहीं रहे। ऐसे में भाजपा की सरकार बनने के बाद वह खींचतान समाप्त हो जाएगी और उम्मीद बनी है कि कुछ बेहतर और उल्लेखनीय काम हो सकेंगे। मगर नई सरकार के सामने चुनौतियां भी कम न होंगी। आम आदमी पार्टी सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जो काम किए हैं, उससे बेहतर काम करके दिखाना होगा। फिर शहर की साफ-सफाई, जलभराव आदि जैसी समस्याओं से निपटना हर वर्ष की चुनौती है। नगर निगम के साथ किस तरह तालमेल बिठा कर वह इन मसलों को हल करने का प्रयास करेगी, उसी आधार पर उसका जनाधार मजबूत हो सकता है।

घरेलू हिंसा कानून का दुरुपयोग, नाहक आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- बेगुनाहों को न फंसाएं

इसमें कोई दोराय नहीं कि महिलाओं को घरेलू हिंसा और अन्य प्रकार के उत्पीड़न से बचाने के लिए जो कानून बने हैं, वे अपने उद्देश्य और प्रभाव के स्तर पर वास्तव में लागू होने चाहिए। मगर इन कानूनों के पालन के साथ यह जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है कि जाने या अनजाने इस कानून का किसी रूप में दुरुपयोग न हो। विडंबना यह है कि कई बार कानूनों का इस्तेमाल मुख्य आरोपी के साथ ही ऐसे लोगों पर भी कर दिया जाता है, जो संबंधित मामले में भागीदार नहीं होते। ऐसे मामलों में अगर किन्हीं वजहों से ऐसे आरोप गलत साबित होते हैं, तो न केवल पीड़ित को असुविधाजनक स्थिति का सामना करना पड़ता है, बल्कि कानूनों के बेजा इस्तेमाल का सवाल भी उठता है। शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान घरेलू हिंसा के मामलों से अत्यंत संवेदनशीलता के साथ निपटने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि किसी आरोपी के परिवार के सदस्यों को आपराधिक मामले में विशिष्ट आरोप के बिना व्यापक रूप से नहीं घसीटा जा सकता। महिलाओं के उत्पीड़न की रोकथाम के लिए बने कानूनों का मकसद समाज में महिलाओं के खिलाफ कई स्तर पर पलने वाले हिंसक रवैये से उन्हें सुरक्षा देना है। अगर किन्हीं हालात में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न की घटना होती है और पीड़ित उन्हीं कानूनों का सहारा लेकर न्याय की मांग करती है, तो यह स्वाभाविक है। लेकिन अगर इस क्रम में कठघरे में वैसे लोग भी आ जाएं, जिनकी कोई भूमिका न हो, तो ऐसे में कानूनों के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठते हैं। उत्पीड़न के समय पीड़ित को बचाने के लिए आगे न आने पर संवेदनशीलता, मानवीयता और जिम्मेदारी के सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए किसी को कानून के कठघरे में खड़ा करने की मंशा को उचित नहीं कहा जा सकता। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सामाजिक पूर्वाग्रहों की वजह से कई बार ऐसे हालात पैदा होते हैं, जिनकी शिकार महिलाएं होती हैं। ऐसे में कानून का सहारा लेने के मामले में ईमानदारी के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी अहम है।

आज का कार्टून

ग्लोबल वार्मिंग से जीडीपी को भी खतरा!

जलवायु के प्रति सबसे संवेदनशील देशों में से एक भारत को अपनी कृषि, जल सुरक्षा और शहरी लचीलेपन के लिए गंभीर खतरों का सामना करना पड़ रहा है. बढ़ते तापमान और बदलते मौसम के कारण पहले से ही फसल की पैदावार में गिरावट आ रही है. खाद्य सुरक्षा को खतरा है और पानी की कमी बढ़ रही है. इन जलवायु प्रभावों का खामियाजा सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों को उठाना पड़ रहा है, जिसमें छोटे किसान, प्रवासी श्रमिक और पारिस्थितिकी रूप से कमजोर क्षेत्रों में रहने वाले लोग शामिल हैं. आजीविका की सुरक्षा और दीर्घकालिक लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए एक अधिक संतुलित दृष्टिकोण-जिसमें शमन और अनुकूलन पर समान जोर दिया जाता है वो आवश्यक है.

अपर्णा राय

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अपने बजट आवंटन में मामूली 2.47प्रतिशत की वृद्धि मिली है. औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन, जलवायु अनुकूलन और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए धन की कमी होगी. हालांकि सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों पर बढ़ता खर्च स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने का संकेत देता है. लेकिन, यह बजट भारत के जलवायु एजेंडे के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाने में विफल दिख रहा है.

जलवायु संकट से जीडीपी को नुकसान: भारत ने महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसका लक्ष्य 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन और 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 50त्न की कमी लाना है. इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ-साथ विकसित भारत के लिए लचीली और समावेशी विकास रणनीतियों को अपनाना होगा. यदि जलवायु जोखिम कम नहीं किये गये तो भारत को जलवायु संकट के कारण 2070 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद का 24.7त्न कम होने की आशंका है.

अमेरिका के बाद भारत की भूमिका बढ़ी: संयुक्त राज्य अमेरिका के पेरिस समझौते से बाहर आने की घोषणा के बाद, दुनिया तेजी से भारत को वैश्विक जलवायु नेता के रूप में देख रहा है. हालांकि, जलवायु परिवर्तन पर रोक को लेकर भारत का मौजूदा बजट उम्मीदों से कम है. महत्वपूर्ण जलवायु क्षेत्रों के लिए न्यूनतम बजटीय सहायता के साथ, भारत अपने जलवायु कार्रवाई प्रयासों को सार्थक रूप से कैसे आगे बढ़ा सकता है? जलवायु संतुलन को बनाये रखने के लिए कौन-कौन से संरचनात्मक और रणनीतिक ढांचे को लागू किया जाना चाहिए?

नीति निर्माण में बदलाव की जरूरत: सबसे पहले, भारत को नीति निर्माण में सार्थक बदलाव की आवश्यकता है. जिसके लिए विकास को मापने के तरीके को फिर से परिभाषित करना होगा. भारत के सामने मौजूद मूलभूत चुनौतियों में से एक जलवायु नीतियों और आर्थिक रणनीतियों के बीच एकीकरण की कमी है. बजट बुनियादी ढांचे के विस्तार और औद्योगिक निवेश द्वारा संचालित आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच चल रहे संघर्ष को उजागर करता है. जलवायु संतुलन बनाये रखने के लिए सरकार की घोषणाएं, आर्थिक विकास पर की गई घोषणाओं से अलग हैं. जिससे दोनों के बीच विरोधाभास बना हुआ है. दृष्टिकोण में बदलाव ज़रूरी है.

जीडीपी पर निर्भरता कम हो: जलवायु संतुलन के लिए की जा रही पहल को आर्थिक बाधा के रूप में नहीं बल्कि विकास गुणक के रूप में देखा जाना चाहिए. भारत को आर्थिक प्रगति के प्राथमिक संकेतक के रूप में जीडीपी पर निर्भरता से आगे बढ़ना चाहिए. एक अधिक व्यापक ढांचा जिसमें कार्बन तीव्रता, संसाधन दक्षता और जलवायु लचीलापन जैसे स्थिरता मीट्रिक शामिल हैं. दीर्घकालिक विकास की एक स्पष्ट तस्वीर प्रदान करेगा. भारत को अपनी आर्थिक योजना में स्थिरता को शामिल करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विकास पर्यावरणीय और सामाजिक गिरावट की कीमत पर न हो.

ब्लूप्रिंट का अभाव: दूसरा, बजट में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करने से इस असंगत दृष्टिकोण को और उजागर किया गया है. पूंजीगत व्यय के लिए आवंटित 11.5 लाख करोड़ रुपये के साथ, सरकार ने भारत के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है. हालांकि, इस खर्च में जलवायु-लचीले ब्लूप्रिंट का अभाव है. आज शुरू की गई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं आने वाले दशकों के लिए भारत के विकास पथ को आकार देंगी, जिनमें से कई के 2050 से आगे तक चलने की उम्मीद है. एक ऐसा समय जब जलवायु जोखिम तीव्र होने का अनुमान है, बुनियादी ढांचे की योजना में जलवायु लचीलापन को एकीकृत किए बिना, ये परियोजनाएँ कमज़ोरियों को कम करने के बजाय उन्हें और गहरा कर सकती हैं.

जलवायु परिवर्तन से संकट का आकलन: भारत के बुनियादी ढांचे के विस्तार में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक जोखिमों को ध्यान में रखना चाहिए. बड़े पैमाने की परियोजनाओं के कारण अक्सर विस्थापन, भूमि की हानि और आजीविका संबंधी चुनौतियां पैदा होती हैं, जो विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों को प्रभावित करती हैं. फिर भी, बजट में इन प्रभावों को कम करने की रणनीतियों की रूपरेखा नहीं दी गई है. सार्वजनिक निवेश योजना में जलवायु जोखिम आकलन की अनुपस्थिति एक स्पष्ट चूक बनी हुई है. जैसे-जैसे भारत अपने भविष्य के शहरों, राजमार्गों और ऊर्जा ग्रिडों का निर्माण कर रहा है, इन परियोजनाओं में स्थिरता को मुख्यधारा में लाना अनिवार्य है.

इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा: तीसरा, बजट में एक महत्वपूर्ण कमी यह है कि इसमें अनुकूलन की कीमत पर शमन पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया है. जबकि सौर क्षेत्र और इलेक्ट्रिक वाहनों में निवेश भारत के कम कार्बन संक्रमण लक्ष्यों के अनुरूप है, अनुकूलन उपायों पर कम ध्यान दिया जाता है. जैव विविधता संरक्षण के लिए वित्तपोषण स्थिर हो गया है, और तटीय लचीलेपन के लिए आवंटन- जो बढ़ते समुद्री स्तरों के प्रति भारत की भेद्यता को देखते हुए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है में कमी आई है. जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष जिसे अनुकूलन प्रयासों का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है. अभी भी कम वित्तपोषित है, जिससे कमजोर समुदायों की रक्षा करने की क्षमता सीमित है.

फसल की पैदावार में गिरावट: जलवायु के प्रति सबसे संवेदनशील देशों में से एक भारत को अपनी कृषि, जल सुरक्षा और शहरी लचीलेपन के लिए गंभीर खतरों का सामना करना पड़ रहा है. बढ़ते तापमान और बदलते मौसम के कारण पहले से ही फसल की पैदावार में गिरावट आ रही है. खाद्य सुरक्षा को खतरा है और पानी की कमी बढ़ रही है. इन जलवायु प्रभावों का खामियाजा सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों को उठाना पड़ रहा है, जिसमें छोटे किसान, प्रवासी श्रमिक और पारिस्थितिकी रूप से कमजोर क्षेत्रों में रहने वाले लोग शामिल हैं. आजीविका की सुरक्षा और दीर्घकालिक लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए एक अधिक संतुलित दृष्टिकोण-जिसमें शमन और अनुकूलन पर समान जोर दिया जाता है वो आवश्यक है.

पर्यावरण लाभ वाली परियोजना: चौथा, मौजूदा जलवायु वित्त ढांचे की एक बड़ी कमजोरी अस्थिर निजी निवेशों पर इसकी अत्यधिक निर्भरता है. बजट इस चुनौती से निपटने के लिए बहुत कम करता है. बड़े पैमाने पर जलवायु वित्त जुटाने के लिए, भारत को एक मजबूत विनियामक ढांचा लागू करना चाहिए जो जलवायु-केंद्रित परियोजनाओं में सार्वजनिक और निजी दोनों तरह की पूंजी को आकर्षित करे. एक टिकाऊ वित्त वर्गीकरण की स्थापना, सख्त प्रकटीकरण मानदंडों के साथ, निवेशकों के लिए बहुत जरूरी स्पष्टता प्रदान करेगी. यह सुनिश्चित करेगी कि पूंजी ठोस पर्यावरणीय लाभ वाली परियोजनाओं की ओर प्रवाहित हो.

बजट आवंटन बढ़ाये जाने की जरूरत: भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं के लिए बजट आवंटन बढ़ाये जाने की जरूरत है. जलवायु लचीलापन और सतत विकास हासिल करने के लिए संरचनात्मक नीतिगत बदलाव, विकास योजना में जलवायु कार्रवाई का एकीकरण और शमन, अनुकूलन और वित्त के बीच एक संतुलन की जरूरत है. इन उपायों के बिना, महत्वाकांक्षा और क्रियान्वयन के बीच की खाई को पाटना एक कठिन लड़ाई बनी रहेगी.

बार-बार अवकाश से बिगड़ता है सीखने का लय

बुनियाद को हम मजबूत तभी कर सकते हैं, जब बच्चों की पढ़ाई के अवसरों को चिंताजनक होने से बचाएं। एक बात और ध्यान में आती है कि प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के एकीकरण से रोज होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान भी स्कूलों की छुट्टियां करनी पड़ती है। अनेक बार कई विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के चलते लंबे समय तक बच्चों की पढ़ाई ठप हो जाती है। सच यह है कि स्कूली शिक्षा में शिक्षकों की कमी देश भर में एक बड़ी समस्या है। इसकी वजह से देश की शिक्षा व्यवस्था और शैक्षिक गुणवत्ता जिस स्तर पर प्रभावित होती है, उसे लेकर कई बार सवाल उठाए गए हैं। लेकिन इस व्यापक समस्या को दूर करना शायद ही किसी सरकार को प्राथमिक और जरूरी लगता है।

राजेंद्र जोशी

लोकतंत्र में सरकार के बनाए गए नियमों से ही जनता को चलना होता हैं। सरकार के नियमों से जीवनयापन की जिम्मेदारी लोक उठाता है। मगर सरकार जब नियम-कानून- कायदे बनाती है, तब उससे हर वर्ग और हर विभाग के लिए उसके अनुरूप कानून और कायदे बनाए जाने की अपेक्षा रहती हैं। विडंबना यह है कि शिक्षा और स्थानीय निकायों को एक ही लकड़ी से हांकने की कोशिश हो रही है। आमतौर पर सरकार में बैठे नौकरशाहों को संबंधित क्षेत्र में हर विषय का विशेषज्ञ माना जाता है।

मगर सच यह है कि लोक के प्रतिनिधि जब तंत्र में आते हैं तो उन्हें यह देखना चाहिए कि शिक्षा से संबंधित निर्णय अभिभावकों और शिक्षाविदों की सलाह से लिए जाएं। इसके बाद शैक्षणिक सत्र या 'कैलेंडर' क्षेत्र विशेष के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। देश के अलग-अलग राज्यों में एक ही समय में मौसम का तापमान अलग रहता है। वहां के मौसम को देखते हुए ही क्षेत्र विशेष में छुट्टियों का फार्मूला तय किए जाने की जरूरत है। पिछले दिनों एक खबर सामने आई थी कि जिला कलेक्टर सर्दी को मद्देनजर रखते हुए संबंधित जिले में स्कूलों की छुटियां और समय में परिवर्तन कर सकते हैं। भारत सरकार और राज्य सरकारें शिक्षा सत्र में छुट्टियों के मामले में लगभग एक जैसा ही रुख रखती हैं। जबकि शिक्षा विभाग में अन्य विभागों से छुट्टियां अधिक होती हैं। पिछले दिनों एक जानकारी सामने आई कि स्कूलों में बच्चों के कुल तीन सौ पैंसठ दिन में से एक सौ पैंतालीस दिन अवकाश में बीत जाते हैं। इसके अलावा आकस्मिक अवकाश की व्यवस्था अलग है।

ऐसे में जरूरत इस बात की है कि बच्चों के अध्ययन में कोई कमी न हो, इसके लिए छुट्टियों का तालमेल कुछ इस तरीके से बिठाया जाए, ताकि छुट्टियां कम से कम हों। दरअसल, एक विचार यह भी रहा है कि इतने अधिक दिन स्कूल बंद रहने से बच्चों के भीतर सीखने और शिक्षण के बाकी स्तर की नींव कमजोर हो जाती है। इस सिरे से देखें तो अगर पढ़ाई-लिखाई के मामले में बच्चों की नींव कमजोर होगी तो इसका सीधा असर देश के भविष्य पर पड़ेगा। इसके अलावा, अलग-अलग कारणों से जिस तरह स्कूलों में बार-बार छुट्टियां या नियमित कक्षाएं बाधित होती हैं, शिक्षकों को अन्य कार्यों में लगाया जाता है, उससे बच्चों की पढ़ाई बाधित होती हैं।

यहां यह भी सोचने की बात है कि बदलते मौसम चक्र में ज्यादा बारिश या गर्मी या ठंड कोई नई बात नहीं रही है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से अचानक इस वजह से स्कूलों को बंद करने की घोषणा की जाती है, वह विचित्र है। मौसम के बारे में अब पूर्वानुमान से लेकर इस संबंध में आकलन किए जाने को लेकर वैज्ञानिक आधार पहले से मौजूद होते हैं। सवाल है कि स्कूल चलने देने या बंद करने के मामले में मौसम को अगर वजह माना जाता है तो इस वजह को पहले से ध्यान में क्यों नहीं रखा जाता। बदलते मौसम परिवर्तन को पहले से स्कूलों के समय में परिवर्तन किया जाना चाहिए। बार-बार छुट्टियां करना, बेवजह स्कूल बंद रखना उचित नहीं है। फिर ऐसा भी होता है कि कई बार मौसम के बारे में जिस तरह के अनुमान सामने आते हैं, उसके आधार पर घोषणा होती है, मगर अगले दिन से मौसम कई बार वैसा नहीं होता है, जैसा अनुमान लगाया गया होता है। इसके बावजूद इस बात की जरूरत महसूस होती है कि मौसम के मुताबिक स्कूल में समय-सारिणी तय की जाए। मसलन, सर्दी के मौसम के दौरान पहले से ही स्कूल का समय दस बजे से चार बजे तक का रखा जा सकता है, ताकि बच्चों को सर्दी में ठिठुरते हुए स्कूल न जाना पड़े। यह छिपा नहीं है कि अधिक ठंड के मौसम में सुबह छह या सात बजे स्कूल के लिए निकलने की वजह से कई बच्चे बीमार हो जाते हैं और उनकी सेहत के सामने कई तरह के जोखिम रहते हैं। दूसरी ओर, अधिक छुट्टियां होने के कारण बच्चों का शिक्षण बाधित होता है। प्रत्यक्ष शिक्षण में अंतराल ज्यादा होता है तो इससे पढ़ाई-लिखाई का माहौल कमजोर होता है। ऐसे में बच्चे नियमित पढ़ाई-लिखाई से दूर होते जाते हैं।

जरूरत इस बात की है कि बच्चों की शैक्षणिक नींव को प्राथमिक शिक्षा से ही मजबूत किया जाए। शैक्षणिक सत्र को मौसम के अनुकूल प्रभावित करने से पहले हमें व्यापक स्तर पर सोचना होगा। ध्यान रखने की जरूरत है कि यह वह समय है जब दुनिया भर में प्रतिस्पर्धा का दौर चल रहा हैं। ऐसे में हमें भविष्य के भारत के लिए बच्चों से ही उम्मीद हैं। इसके मद्देनजर उनकी शिक्षा की नींव को कमजोर होने से बचाना पड़ेगा। यह बात केवल औपचारिक नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ठोस आकलन है।

बुनियाद को हम मजबूत तभी कर सकते हैं, जब बच्चों की पढ़ाई के अवसरों को चिंताजनक होने से बचाएं। एक बात और ध्यान में आती है कि प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के एकीकरण से रोज होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान भी स्कूलों की छुट्टियां करनी पड़ती है। अनेक बार कई विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के चलते लंबे समय तक बच्चों की पढ़ाई ठप हो जाती है। सच यह है कि स्कूली शिक्षा में शिक्षकों की कमी देश भर में एक बड़ी समस्या है। इसकी वजह से देश की शिक्षा व्यवस्था और शैक्षिक गुणवत्ता जिस स्तर पर प्रभावित होती है, उसे लेकर कई बार सवाल उठाए गए हैं। लेकिन इस व्यापक समस्या को दूर करना शायद ही किसी सरकार को प्राथमिक और जरूरी लगता है। जो शिक्षक सेवा में होते हैं, उनके बीच से भी राजकीय नियमानुसार कुछ शिक्षक लंबे समय तक के लिए छुट्टी पर चले जाते हैं। ऐसे में अन्य शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाती। इन सब कारणों का तो शिक्षा सत्र में कोई हिसाब-किताब नहीं है।

गुजरात इंजेक्ट (केरल) लिमिटेड ने तीसरी तिमाही के मजबूत नतीजों की घोषणा की

वडोदरा एजेंसी। बीएसई लिस्टेड, गुजरात इंजेक्ट (केरल) लिमिटेड (बीएसई- 524238) देश में कृषि उत्पादों के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध अग्रणी कंपनी है। कंपनी ने दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही में अपने शुद्ध लाभ में 4500 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की। कंपनी थोक सब्जियों और फलों का व्यापार करने में माहिर है। यह सीधे किसानों से ताजा उपज प्राप्त करती है और गुणवत्ता, ताजगी और दोषरहित आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करते हुए इसे दुकानदारों तक पहुंचाती है। गुजरात इंजेक्ट (केरल) का दिसंबर-2024 तिमाही का शुद्ध लाभ 21.16 लाख रुपए था, जो गत वर्ष की हुए शुद्ध लाभ 0.46 लाख की तुलना में 45 गुना ज्यादा अधिक रहा। इसके अलावा, दिसंबर-2024 तिमाही में कंपनी की आय 315.23 लाख रुपए थी, जो गत वर्ष इसी समयावधि में 21.59 लाख दर्ज की गई थी, यह कंपनी की 1,360 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्शाता है। दिसंबर-2024 को समाप्त नौ महीनों के लिए, गुजरात इंजेक्ट (केरल) की आवक 1,480.86 लाख रुपए दर्ज की गई है जो पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि में 36.96 लाख रुपए थी। यानी यह 3,906 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। साथ ही, नौ महीने की अवधि में कंपनी का शुद्ध लाभ 94.40 लाख रुपए था, जो पिछले वर्ष इसी समयावधि में 4.48 लाख रुपए से 2,007 प्रतिशत अधिक है। गुजरात इंजेक्ट (केरल) के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपए है और शुक्रवार, 7 फरवरी, 2025 को इसका समापन मूल्य 27.13 रुपए था। पिछले 52 हफ्तों में, शेयर 28 रुपए की उच्च और 8.74 रुपए का न्यूनतम स्तर देखा गया है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 38.04 करोड़ रुपए है। पिछले वर्षों में उल्लेखनीय गतिविधि की कमी के बाद, कंपनी ने पिछले दो वर्षों के दौरान अपने प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार दिखाया है। कंपनी का बेहतर प्रदर्शन उसके शेयर मूल्य में भी परिलक्षित होता है, जिसमें पिछले महीने 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके अलावा ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ गया है, जो स्टॉक में सकारात्मक गति का संकेत दे रहा है।

वार्डविज़र्ड इनोवेशन्स एण्ड मोबिलिटी लिमिटेड ने दर्ज की 3830 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री

वड़ोदरा , एजेंसी। ब्राण्ड्स 'जॉय ई-बाईक' और 'जॉय ई-रिक' के तहत इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली अग्रणी निर्माता वार्डविज़र्ड इनोवेशन्स एण्ड मोबिलिटी लिमिटेड ने जनवरी 2025 में 3830 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बेचे हैं, जिसमें हाई-स्पीड एवं लो-स्पीड मॉडल शामिल हैं। इस दृष्टि से कंपनी ने जनवरी 2024 की तुलना में 18.76 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की है, जब 3225 युनिट्स बेची गई थीं।

इसके अलावा, कंपनी ने 'जॉय ई-रिक' ब्राण्ड' के तहत 22 इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन बेचे, जिसमें पैसेंजर और कमर्शियल वाहन शामिल हैं। इस परफोर्मेन्स पर बात करते हुए श्री यतिन गुप्ते, चेयरमैन एवं प्रबन्ध निदेशक, वार्डविज़र्ड इनोवेशन्स एण्ड मोबिलिटी लिमिटेड ने कहा, ''हमने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री में 18.76 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 2025 की शानदार शुरूआत की है, जो स्थायी परिवहन को बढ़ावा देते हुए जॉय ई-बाईक ब्राण्ड में उपभोक्ताओं के बढ़ते भरोसे को दर्शाता है। सरकार ईवी सिस्टम को सशक्त बनाने तथा स्वच्छ परिवहन को सशक्त बनाने पर ध्यान दे रही है, ऐसे में हम उद्योग जगत में स्थायी विकास को लेकर आशावादी हैं। हमारे इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों के बढ़ते अडॉप्शन से स्पष्ट है कि किफ़ायती एवं पर्यावरण के अनुकूल परिवहन समाधानां की मांग बढ़ रही है। वार्डविज़र्ड में हम हरित भविष्य की ओर भारत के रूपान्तरण को समर्थन प्रदान करते हुए इनोवेशन्स के लिए प्रतिबद्ध हैं।' उद्योग जगत में मुख्य प्लेयर के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत बनाते हुए वार्डविज़र्ड इनोवेशन्स एण्ड मोबिलिटी ने हाल ही में न्यूयॉर्क की लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी कंपनी सी4वी के साथ एमओयू साईन किया था, गौरतलब है कि सी4वी बैटरी सैल डिज़ाइन एवं ऑप्टिमाइज़ेशन में विशेषज्ञ है।

ट्रंप ने स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया

अमेरिका के इस फैसले से भारत के एक्सपोर्ट पर भी असर पड़ेगा

नई दिल्ली, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक नया टैरिफ लगाते जा रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि वह स्टील और एल्युमिनियम के आयात पर 25 फीसदी शुल्क लगाएंगे। यह फैसला भारत और अमेरिका के बीच व्यापार के एक पुराने विवादित मुद्दे से जुड़ा है। हालांकि यह शुल्क सभी देशों से होने वाले स्टील और एल्युमिनियम के आयात पर लगाया जाएगा।

अमेरिका के इस फैसले से भारत के 1.27 अरब डॉलर (करीब 11 हजार करोड़ रुपये) के एक्सपोर्ट पर असर पड़ सकता है। भारत ने अमेरिका को वित्त वर्ष 2023-24 में 1.27 अरब डॉलर का स्टील और एल्युमिनियम एक्सपोर्ट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी बुधवार से अमेरिका के दो दिवसीय दौरे पर होंगे। वह ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ को लेकर कुछ चर्चा हो सकती है।

दोनों देशों के बीच रहा है कुछ विवाद- स्टील और एल्युमिनियम का व्यापार भारत और अमेरिका के बीच हमेशा से एक विवाद का विषय रहा है। अमेरिका, भारत पर इन निर्यातों को सब्सिडी देने का आरोप लगाता रहा है। सब्सिडी का मतलब होता है कि सरकार अपनी कंपनियों को पैसे देती है ताकि वो कम दाम पर सामान बेच सकें।

साल 2023 में पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान दोनों देशों ने विश्व व्यापार संगठन के सामने धातुओं से जुड़े छह विवादों को सुलझाने पर सहमति जताई थी। लेकिन अक्टूबर में अमेरिका ने एल्युमिनियम आयात की कुछ श्रेणियों पर 39.5 फीसदी तक का शुल्क लगा दिया था। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप द्वारा घोषित 25 फीसदी शुल्क इन पर कैसे लागू होगा।

क्या पड़ेगा असर- भारत अमेरिका को जितना स्टील और एल्युमिनियम एक्सपोर्ट करता है, स्टील की हिस्सेदारी कम है। भारत कुल एक्सपोर्ट में करीब 5 फीसदी की अमेरिका को बेचता है। लेकिन एल्युमिनियम में मामला बड़ा है। भारत करीब 12 फीसदी एल्युमिनियम अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। अगर अमेरिका इस पर टैरिफ लगाता है तो इससे एक्सपोर्ट पर बड़ा असर दिखाई देगा।

अस्पताल, मेडिकल कॉलेज में हेल्थकेयर पर 6000 करोड़ खर्च करेगा अडानी समूह

नई दिल्ली, एजेंसी। गौतम अडानी समूह हेल्थ सेक्टर में बड़ा निवेश करने वाला है। यह समूह मेयो क्लिनिक के साथ साझेदारी में हेल्थ इंफ्रा पर 6,000 करोड़ रुपये खर्च करेगा। इसके तहत मुंबई और अहमदाबाद में दो 1,000 बिस्तर वाले मल्टी-स्पेशियल्टी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। समूह ने इस पहल के लिए अमेरिका की मेयो क्लिनिक ग्लोबल कंसल्टिंग को रणनीतिक सलाहकार के रूप में चुना है। मेयो क्लिनिक इन अस्पतालों में संगठनात्मक उद्देश्यों, क्लिनिकल प्रक्रियाओं, डिजिटल, आईटी और हेल्थ सर्विस की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद करेगा।

गौतम अडानी ने क्या कहा- गौतम अडानी ने कहा- दो साल पहले, मेरे 60वें जन्मदिन पर मुझे उपहार के रूप में मेरे परिवार ने हेल्थ सर्विस, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के

लिए 60,000 करोड़ रुपये देने का वादा किया था। इसी के तहत अडानी हेल्थ सिटी का प्रोजेक्ट है। यह प्रोजेक्ट भारतीय समाज के हर वर्ग के लोगों को किफायती, विश्वस्तरीय हेल्थ सर्विसेज देने की दिशा में अहम होगा।

क्या है अडानी समूह का प्लान

अडानी समूह की ओर से जारी बयान में कहा गया है- समूह पूरे भारत में समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए किफायती, विश्वस्तरीय चिकित्सा देखभाल और चिकित्सा शिक्षा की लागत को पूरी तरह से वहन करेगा। इसी के तहत अहमदाबाद और मुंबई में 6,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे। बयान में विस्तृत जानकारी दिए बिना कहा गया कि गौतम अडानी ने भारत के अलग-अलग शहरों और कस्बों में ऐसे अन्य इंटीग्रेटेड 'अडानी हेल्थ सिटी' की योजना बनाई है। इन इंटीग्रेटेड कैंपस में प्रत्येक में 1,000 बिस्तर वाले मल्टी-स्पेशियल्टी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज होंगे।

मेडिकल कॉलेज की बात करें तो इसमें हर साल 150 अंडरग्रेजुएट, 80 से अधिक रेजिडेंट और 40 से अधिक फेलो को प्रवेश मिलेगा। इसमें स्टेप-डाउन और ट्रांजिशनल केयर फैसलिटीज और अत्याधुनिक रिसर्च सेंटर शामिल होंगे। समूह ने बताया कि इस पहल का मकसद सभी तरह के सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की सेवा करना, चिकित्सकों की अगली पीढ़ी को प्रशिक्षित करना और रिसर्च, एआई और बायोमेडिकल एरिया पर ध्यान केंद्रित करना है।

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग 2025 की बड़ी तैयारी, 1.18 लाख अभ्यर्थी, नकल रोकने के लिए उड़न दस्ते तैनात

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 की पूरी तैयारी कर ली है, जो 16 फरवरी को प्रदेश के सभी 52 जिलों में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में कुल 1 लाख 18 हजार अभ्यर्थी भाग लेंगे। मुख्य परीक्षा (मेन्स) जून में प्रस्तावित है और इंटरव्यू भी इसी वर्ष आयोजित किए जाने की योजना है।

दो पालियों में होगी परीक्षा

परीक्षा के लिए इंदौर में 25,700 अभ्यर्थी उपस्थित होंगे, जहां यह दो पालियों में संपन्न होगी। पहली पाली सुबह 10ः00 से 12ः00 बजे तक होगी, जबकि दूसरी पाली दोपहर 12ः15 से 4ः15 बजे तक चलेगी। इस बार कुल 158 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जबकि पिछले वर्ष 2024 में केवल 110 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। पिछली परीक्षा में 1 लाख 84 हजार आवेदन प्राप्त हुए थे, लेकिन वास्तविक परीक्षा में 1 लाख 32 हजार अभ्यर्थियों ने भाग लिया था।

इंदौर में सर्वाधिक 71 केंद्र

MPPSC इंदौर के ओएसडी डॉ. आर. पंचभाई के अनुसार, प्रदेशभर में परीक्षा के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। इंदौर में इस परीक्षा के लिए सर्वाधिक 71 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें प्रमुख सरकारी कॉलेज जैसे होलकर साइंस कॉलेज और अटल बिहारी कॉलेज शामिल हैं। आयोग इस वर्ष दिसंबर तक राज्य सेवा परीक्षा 2023, 2024 और 2025 के अंतिम चयन परिणाम घोषित करने की योजना बना रहा है। परीक्षा में नकल रोकने के लिए उड़न दस्तों की तैनाती की गई है, जो अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर निगरानी रखेंगे। साथ ही, प्रश्न पत्र की गोपनीयता सुनिश्चित करने और किसी भी प्रकार की त्रुटियों को रोकने के लिए भी विशेष सतर्कता बरती जाएगी।

मस्क ने ओपनएआई को खरीदने का दिया प्रस्ताव, तो सैम ऑल्टमैन ने एक्स की लगा दी बोली

नई दिल्ली, एजेंसी। एलन मस्क के नेतृत्व वाले एक निवेशक समूह ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) स्टार्टअप ओपनएआई को 97 अरब डॉलर में खरीदने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने मस्क के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। साथ ही ऑल्टमैन ने ये भी कहा कि अगर आप चाहते हैं तो हम ट्विटर को 9.7 अरब डॉलर में जरूर खरीद सकते हैं। गौरतलब है कि एलन मस्क ने साल 2022 में ही ट्विटर को 44 अरब डॉलर में खरीदा था और बाद में ट्विटर का नाम बदलकर एक्स कर दिया था।

सैम ऑल्टमैन ने उल्टा एलन मस्क को ट्विटर खरीदने का दिया ऑफर- एलन मस्क के खुद के एआई स्टार्टअप एक्सएआई और निवेशक फर्मों के एक समूह ने मिलकर चैटजीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपनएआई को 97 अरब डॉलर में खरीदने की इच्छा जताई है। एलन मस्क के वकील मार्क टोबरॉफ ने बताया कि मस्क ओपनएआई को एक गैर लाभकारी रिसर्च लैब में बदलना चाहते हैं। इस प्रस्ताव पर सैम ऑल्टमैन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि नो थैंक्यू, लेकिन अगर आप चाहें तो हम आपके ट्विटर को 9.74 अरब डॉलर में खरीद सकते हैं।

गौरतलब है कि साल 2015 में एलन मस्क और सैम ऑल्टमैन ने मिलकर ही ओपनएआई स्टार्टअप की शुरुआत की थी। बाद में ओपनएआई का नेतृत्व करने को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया और आखिरकार साल 2018 में मस्क ने ओपनएआई के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया।

बैंकों में नकदी की किल्लत, कर्ज की किस्त घटने में लग सकते हैं तीन माह; रेपो दर घटने के बाद अहम बदलाव

नई दिल्ली, एजेंसी। आरबीआई ने करीब पांच साल के बाद पहली बार रेपो दर में 0.25 फीसदी की कटौती कर विभिन्न प्रकार के कर्ज लेने वाले ग्राहकों को राहत तो दी, लेकिन इसका लाभ मिलने में अब भी दो से तीन महीने का समय लग सकता है। इसकी प्रमुख वजह है...बैंकों के पास नकदी की किल्लत। इस समस्या से बाहर निकलने के लिए बैंक रेपो दर में कटौती के बाद भी ज्यादा ब्याज देकर जमा जुटाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इससे बैंकों को जरूर फायदा होगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि जिन लोगों ने फिक्स्ड दर पर कर्ज लिया है, उन्हें रेपो दर में कटौती का लाभ पाने में बहुत अधिक समय लग सकता है। हालांकि, फ्लोटिंग दर पर कर्ज लेने वाले ग्राहकों को इसका लाभ जल्द मिलने की उम्मीद है। फिर भी, दोनों प्रकार के ग्राहकों को इसका फायदा मिलने में दो-तीन महीने लग सकते हैं। इसके बाद ही उनकी मासिक किस्त (ईएमआई) में कमी आएगी।

क्रिसिल रेटिंग्स के वरिष्ठ निदेशक अजीत वेलोनी ने कहा, फ्लोटिंग दर वाले कर्जों का बढ़ता अनुपात कुल लोन बुक का 40 फीसदी से अधिक पहुंच गया है और यह बाहरी दरों पर आधारित है। इसलिए, उधारकर्ताओं को ब्याज दर घटने के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। बंधन एएमसी में फिक्स्ड इनकम के प्रमुख सुयश चौधरी ने कहा, ब्याज दर में कटौती के लिए बैंकों को पहले अपनी वित्तीय स्थिति की समीक्षा करनी होगी, जैसा वे हर बार करते हैं। नए वित्त वर्ष यानी 2025-26 की पहली तिमाही जैसे ही शुरू होगी और नकदी के मोर्चे पर सुधार होगा, बैंक कर्ज की ब्याज दरों को कम करना शुरू कर सकते हैं।

2.50 लाख करोड़ घट सकती है नकदी- विशेषज्ञों ने भविष्य में नकदी की स्थिति को लेकर चिंता जताई है। फरवरी, 2025 में सुधार दिखाने के बाद अगर आरबीआई अतिरिक्त तरलता उपाय लागू नहीं करता है, तो मार्च, 2025 के अंत तक प्रणाली की नकदी में 2.50 लाख करोड़ रुपये तक कमी आ सकती है। इससे बैंकों पर दबाव और ज्यादा बढ़ेगा, जिससे ब्याज दरें घटने में देरी होगी। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे ने कहा, बाहरी बेंचमार्क से जुड़े ऋणों पर दर में कटौती का तत्काल असर हो सकता है।

जमाकर्ताओं के लिए मुनाफा कमाने का मौका- वर्तमान जमाकर्ताओं पर रेपो दर घटने या बढ़ने का कोई असर नहीं होगा। लेकिन, बैंकों को मिलने वाले नए जमा पर इसका असर जरूर देखने को मिलेगा।विशेषज्ञों का कहना है कि जमा को लेकर बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा का माहौल है। ऐसे में बैंक अगर जमा पर ब्याज दरें घटाते हैं, तो ग्राहक अपना पैसा निकालकर किसी और साधन में निवेश कर सकते हैं। ऐसे में बैंक इन जमाओं को बनाए रखने और नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कुछ और समय तक ऊंची ब्याज दर को बनाए रख सकते हैं।

उद्यमशीलता और स्टार्टअप के ओरिएंटल यूनिवर्सिटी में गुर बताए

ओरिएंटल यूनिवर्सिटी के बिजनेस इन्क्यूबेशन सेंटर में एंटरप्रेन्योरशिप जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

इंदौर। उच्च शिक्षित समाज में इन्क्यूबेशन रणनीति का बहुत महत्व है। एमएसएमई स्टार्टअप के लिए कई योजनाएं संचालित कर रहा है और इनका क्रियान्वयन किया जा रहा है।

यह विचार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के सहायक निदेशक प्रोफ़ेसर आर के मोहनानी ने प्रकट किए। ओरिएंटल यूनिवर्सिटी के बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर में एंटरप्रेन्योरशिप जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सीईईडी के प्रोफेसर-इन-चार्ज डॉक्टर स्वामीनाथन आर, आईआईटी इंदौर, डॉक्टर अशोकन पापु, सीएसआईआर एमपीआरआई ने विद्यार्थियों को उद्यमशीलता और स्टार्टअप पर बहुउपयोगी जानकारी दी। डॉ. अशोकन पापु ने नवाचार और अनुसंधान फ़ेलोशिप पर जानकारी दी। एमएसएमई के सहायक निदेशक श्री गौरव गोयल और आईआईटी इंदौर के एसीई फाउंडेशन की सुश्री सोनल राय का कार्यक्रम में विशेष सहयोग रहा। ओरिएंटल यूनिवर्सिटी के बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर की मेजबानी में हुए कार्यक्रम में विद्यार्थियों की जिज्ञासा का समाधान किया गया। कार्यक्रम में चांसलर प्रवीण ठकराल, प्रो. चांसलर गौरव ठकराल, प्रो. चांसलर प्रोफेसर (डॉ.) ध्रुव घई, कुलपति प्रोफेसर (डॉ.) सुनील के सोमानी, रजिस्ट्रार डॉ. प्रद्युमन यादव एवं बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर की प्रमुख प्रोफेसर (डॉ.) गरिमा घई का विशेष मार्गदर्शन रहा।

UK govt offers Indian students chance to study, live through this special visa route

The United Kingdom government has started the application process for the UK-India Young Professionals Scheme 2025. The scheme offers residents and Indians the opportunity to live, study, travel, and work in both the UK and India for up to two years. Indian nationals aged between 18-30 must enter the ballot at –gov.uk– to be considered for one of the 3,000 spots available under the scheme.

The ballot is scheduled to open at 2:30 pm (IST) between February 18 and February 20 at the same time. Applicants do not need to pay to enter the ballot. Successful entries will be picked at random by the concerned authorities. Those under the Youth Mobility Scheme visa will not be selected.

–Applicants must be at least 18 years old on the date they plan to travel to the UK.

–They must have proof of £2,530 which is Rs 2,70,824 (approx) in savings to support themselves in the UK.

–Should not have any children under the age of 18 who live with you or who you're financially responsible for

–They must also qualify for a UK bachelor's degree level or above and must be between 18-30.

–Applicants should ensure they meet all eligibility requirements before entering the ballot, as mentioned in the release.

–They must have Rs 2,50,000 in their bank account for a minimum period of 30 days.

For more information, they can visit the official website–www.gov.uk/india-young-professionals-scheme-visa/eligibility

UK-India Young Professionals Scheme 2025: Process

The YPS ballot for Indian nationals wanting to travel to the UK is free to enter. Those selected from the ballot will be notified via email within two weeks of the ballot closing and will be invited to apply for the visa.

They will then have 90 days from the date of the email informing them of their success in the ballot to make an application to the UK Home Office via the online application form to provide their biometrics and pay all associated fees, including the visa application fee and immigration health surcharge.

They will need to have the money available for at least 28 days in a row which the day 28 must be within 31 days of applying for this visa.Selected applicants must mandatory return to India after completing two years in the UK under this scheme. There were over 2,100 YPS visas issued to Indian nationals in the year ending December 2023.

JEE Main 2025 Results: Scorecard out at jeemain.nta.nic.in, 12.58 lakh appeared

The National Testing Agency (NTA) has announced the JEE Main 2025 Session 1 result. Earlier, the JEE Main result link at jeemain.nta.nic in displayed an error – '500 Internal Server Error'. Candidates who took the exam can check results at the official website, jeemain.nta.nic.in. Most toppers are from Rajasthan. This year, 14 students got 100 percentile. There are 2 third-gender candidates. Sai Manogna Guthikonda from Andhra Pradesh is the female topper with 100 NTA score.A total of 13,11,544 candidates registered for Paper 1 (B.E./B. Tech.) across different categories and genders. Among them, 4,43,622 were female candidates, with 1,67,790 from the General category, 45,627 from EWS, 42,704 from SC, 13,833 from ST, and 1,73,668 from OBC.

Male candidates accounted for 8,67,920 registrations, including 3,21,419 from General, 96,159 from EWS, 87,550 from SC, 28,778 from ST, and 3,34,014 from OBC. Additionally, two candidates identified as Third Gender, with one from the General category and one from OBC. The highest number of registrations came from the OBC category (5,07,683), followed by General (4,89,210), EWS (1,41,786), SC (1,30,254), and ST (42,611).

NTA conducted the JEE Main 2025 Session 1 exam between January 22 and 30 and announced the final answer keys and has dropped 12 questions. For the dropped questions, all candidates will be awarded full marks.When results are released, candidates should visit the official website, jeemain.nta.nic.in and choose the option "View score card" or "View JEE Main 2025 result. They have to enter application number and password. Complete NTA JEE Main result will appear on the screen, displaying candiadtes scores. It is advised to the candiadtes to print out and save the JEE result page for future reference.

Successful candidates will secure admission into NITs, IIITs, GFTIs, and other participating institutes through JoSAA counselling. Additionally, the top 2.5 lakh qualified candidates of JEE Main 2025 will have the opportunity to appear in JEE Advanced 2025.The registration for the JEE Main April application has been started at jeemain.nta.nic.in. The last date to apply for the Main 2025 April session exam is February 25 (9 pm). The fee payment window will close at 11:50 pm on February 25.

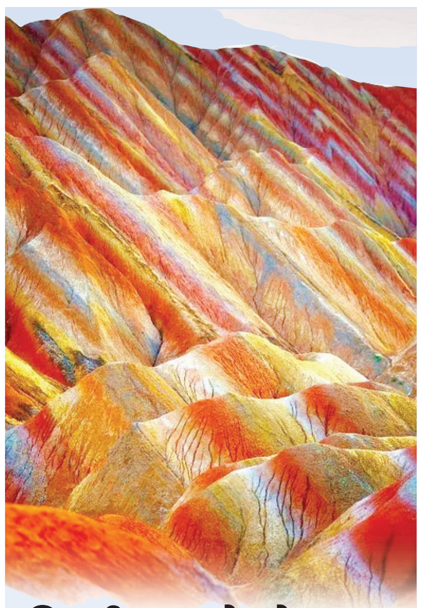

किसी अजूबे से कम नहीं ये सतरंगी पहाड़

दुनिया में ऐसी बहुत सी खूबसूरत जगहें हैं, जो मन को मोह लेती हैं. इन जगहों को देखने और यहां समय बिताने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं. इन जगहों पर जाकर आपको खूबसूरती तो देखने को मिलती ही है, साथ ही कई जगहों पर इतिहास से भी रूबरू होने का मौका मिलता है. इसी कड़ी में आज हम आपको चीन के ऐसे पहाड़ के बारे में बताने जा रहे हैं जो खूबसूरती के मामले में किसी जन्नत से कम नहीं है.

हम सभी जानते हैं कि इंद्रधनुष और पहाड़ हर किसी का मन मोह लेती है. अगर बात करे इंद्रधनुष की तो यह खासतौर पर बारिश के बाद दिखाई देता है. लेकिन क्या आपने कभी ऐसे पहाड़ के बारे में सुना है जो इंद्रधनुष की तरह दिखता हो? जी हां, दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां पर पहाड़ों में इंद्रधनुष जैसे रंग दिखाई देते हैं. सूरज की किरणें पड़ने की इसकी खूबसूरती और भी निखर कर सामने आती है.

पेंटिंग जैसा दिखता है पहाड़

इंद्रधनुष के रंगों में रंगे ये पहाड़ पश्चिमी पेरू और पश्चिमी चीन में हैं. झांगे डेनक्जिया लैंडस्केप के नाम से मशहूर इस जगह पर लाल, नींबू, हरे, मजेंटा आदि रंगों के पहाड़ है. इसके अलावा पेरू में इंद्रधनुष पर्वत औसजेते के पास स्थित है. पहाड़ों पर रंगों की धारधारी परत बनी हुई है. इन पहाड़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे हम कोई पेंटिंग देख रहे हैं. प्राकृतिक रूप से बने इस खूबसूरत पहाड़ों को देखने के लिए दुनियाभर से लोग चीन आते हैं. सात रंगो का होने के कारण इन पहाड़ियों को इंद्रधनुष पर्वत के नाम से जाना जाता है. ये पहाड़ बिलकुल इंद्रधनुष की तरह नज़र आते है. इन पहाड़ियों को किसी इंसान ने नहीं बनाया है, बल्कि इन पहाड़ियों के सात रंग तो कुदरत का करिश्मा है.

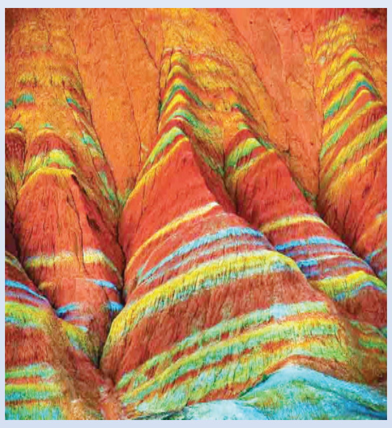

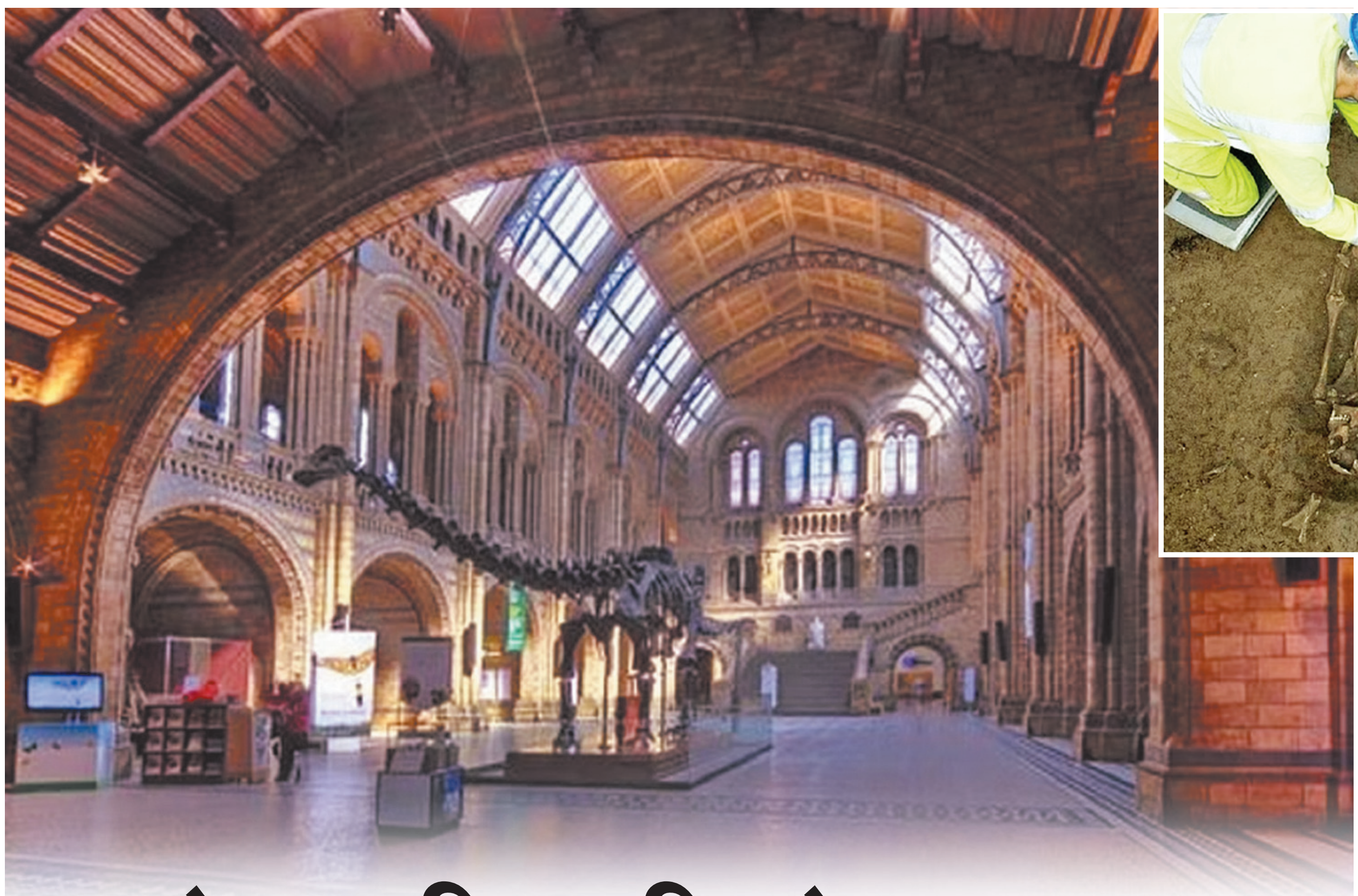

एक ऐसा म्यूजियम जिसके तहखाने में रखा है बेहद ही अजीब किस्म का खजाना

म्यूजियम ऑफ लंदन के तहखाने में बेहद अजीब किस्म का खजाना रखा है। इसके बारे में शायद ही यहां आने वालों को भनक हो। म्यूजियम में ऊपर भले ही आपको चलते हुए रोमन काल से लेकर विक्टोरिया युग में जाने का अहसास हो। तहखाने में जाएंगे तो यकीनन आप चौंक जाएंगे।

इस तहखाने में तरतीब से रखे हुए हैं हजारों गत्ते के बक्से। ठीक वैसे ही जैसे आप, घर बदलते वक्त इस्तेमाल करते हैं, सामान पैक करने के लिए। आप सोचेंगे कि इनमें कुछ खास सामान रखा है। मगर इनके लेबल देखेंगे तो चौंक जाएंगे। इन पर लिखा हुआ है मानव कंकाल। बरसों पहले खत्म हो चुकी जिंदगियों के ये सबूत, लंदन और उसके आस-पास की खुदाई के दौरान मिले हैं। इनमें से कई महज एक सदी पुराने हैं तो बहुत से हजार साल पुराने भी हैं। लंदन म्यूजियम में जमा ये इन कंकालों की देखभाल करने वाली येलेना बेक्कालाक कहती हैं कि ये इंग्लैंड के रोमनकाल से लेकर उन्नीसवीं सदी तक की कहानी सुनाने वाले कंकाल हैं। इन्होंने इतिहासकारों को लंदन का इतिहास यूं बताया है, जैसे कोई बुजुर्ग पुराना किस्सा सुना रहा हो। येलेना बताती हैं कि इन कंकालों की पड़ताल के बाद कई बार इतिहासकारों ने लंदन के इतिहास में फेरबदल किया है। जैसे कि लंदन की बदनाम ब्लैक डेथ यानी प्लेग से हुई मौत से जुड़ी बातों को इन कंकालों के जरिए नए सिरे से जाना समझा गया। माना जाता है कि ब्लैक डेथ के दौरान लंदन शहर पूरी तरह बर्बाद हो गया था। मगर इन कंकालों को देखकर पता चलता है कि प्लेग से मरने वालों की कब्रें बेहद करीने से खोदी गई थीं। यहां कोई भगदड़ का माहौल नहीं दिखता। ये माना जाता है कि मध्य युग में इंसान दांतों की सफाई को लेकर बेपरवाह थे। दांतों की सफाई का चलन, आधुनिक युग की देन माना जाता है। मगर, लंदन में मिले कंकाल बताते हैं कि मध्य युग में लोगों के दांत ज्यादा साफ रहते थे। शायद इसका ताल्लुक हमारे चीनी खाने से है, क्योंकि चीनी ही हमारे दांतों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसी तरह लंदन के इन कंकालों से पता चलता है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का असर लोगों की सेहत पर कैसा पड़ा था। हालांकि अभी इसकी पूरी पड़ताल की जानी बाकी है। लंदन में पिछली कई सदियों में लाखों लोग दफन किए गए हैं। इनमें से ज्यादातर कंकाल, शहर के विकास के लिए होने वाली खुदाई के दौरान निकले हैं। कभी मेट्रो के लिए तो कभी नई इमारतें बनाने के लिए। जानकार कहते हैं कि पहले चर्च ही कब्रिस्तानों की देख-रेख करते थे। कई बार जब चर्चों को अपने स्कूल का विस्तार करना होता था तो वो पुराने कब्रिस्तानों को ही बेच देते थे। इन्हीं की खुदाई के दौरान बहुत से कंकाल मिले। जैसे कि 2011 में चर्च ऑफ इंग्लैंड के प्राइमरी स्कूल के खेल के मैदान की खुदाई में 959 कंकाल मिले।

कई बार पुराने कंकालों को फिर से दफन कर दिया जाता है। ऐसा विकास की प्रक्रिया के दौरान निकले कंकालों के साथ होता है, या फिर कुछ ऐसे कंकाल मिलते हैं जिनसे बहुत ज्यादा जानकारी होने की उम्मीद नहीं होती। फिर भी ऐसे कंकाल काफी मात्रा में मिल जाते हैं जिनसे लंदन के इतिहास की झलक मिल सकती है। ऐसे कंकाल म्यूजियम ऑफ लंदन की देख-रेख में दे दिए जाते हैं। कई बार अच्छे से संवारे हुए बाल या करीने से काटे गए नाखून मिलते हैं। ये अक्सर मध्य युग के होते हैं। अब इन कंकालों को दो हिस्सों में बांटकर इनकी पड़ताल की जा रही है। जैसे कि करीब पंद्रह सौ कंकाल लंदन के हैं और एक हजार कंकाल लंदन के बाहर के। इसी तरह कुछ औद्योगिक क्रांति से पहले के हैं तो कुछ उसके बाद के हैं। इनके बीच तुलना करके दो अलग-अलग दौर के बीच के फर्क को समझने की कोशिश की जा रही है।

कंकालों की पड़ताल में आधुनिक तकनीक काफी मददगार साबित हो रही है। जैसे कि रेडियोग्राफी और सीटी स्कैन। इनकी मदद से उस दौर के इंसानों की सेहत के बारे में अच्छी खासी जानकारी मालूम हो जाती है। जैसे कि औद्योगिक क्रांति से इंग्लैंड के लोगों का रहन-सहन काफी बेहतर हुआ था, लेकिन उन्हें मोटापे और डायबिटीज जैसी बीमारियों से भी दो-चार होना पड़ा। म्यूजियम में रखे कंकालों से ये बातें सामने आई हैं। अक्सर बीमारियों का असर हमारी हड्डियों पर होता है। इनकी महीन जांच से हमें इस असर का अंदाजा होता है। पहले इतिहासकार उस दौर के दस्तावेजों से अंदाजा लगाते थे कि किसी खास दौर में लोगों को किस तरह की बीमारियां होती थीं। लेकिन, दिक्कत ये है कि अलग दौर में डॉक्टर किसी मर्ज को अलग-अलग तरह से समझते और लिखते थे। इसलिए आज कंकालों की पड़ताल से हमारी पुराने दौर के लोगों की बीमारियों की समझ बेहतर हुई है।

कंकालों पर किसी धातु का असर भी दिखता है। जैसे कि एक टकसाल के करीब के कब्रिस्तान से मिले कंकालों पर हरे निशान मिले हैं, जो बताते हैं कि पास ही कोई टकसाल थी। जहां से निकले केमिकल ने कब्रिस्तान में दफन कंकालों पर असर डाला। कंकालों के डीएनए टेस्ट से और भी कई बातें सामने आती हैं, जिनकी पड़ताल में वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। उम्मीद है कि लंदन के म्यूजियम के इस खजाने से, इंग्लैंड के इतिहास के कई नए किस्से सामने आएंगे।

दुनिया में ऐसी कई रहस्यमय जगहें मौजूद है, जो आज भी लोगों के लिए एक रहस्य ही बनी हुई हैं। ऐसी ही एक जगह पुर्तगाल के सिन्तारा में है। यहां एक ऐसा रहस्यमय कुआं है, जिसके अंदर से हमेशा एक अजीब सी रोशनी आती रहती है। वैज्ञानिक भी आज तक ये पता नहीं कर पाए है कि आखिर ये रोशनी कहां से आती है?

इस कुएं से हर वक्त आती रहती है एक रहस्यमय रोशनी, आज तक नहीं सुलझ पाई ये पहेली

इस कुएं को लोग विशिंग वेल भी कहते हैं। कहा जाता है कि यह कुआं लोगों की हर इच्छा को पूरी करता है। यही वजह है कि लोग इस कुएं में सिक्के डालकर अपनी मनोकामना मांगते हैं और उन्हें ये दृढ़ विश्वास होता है कि उनकी इच्छा जरूर पूरी होगी। वैसे आमतौर पर किसी भी कुएं का प्रयोग पानी को संरक्षित करने के लिए किया जाता था, लेकिन यह दुनिया का ऐसा अनोखा कुआं है जिसकी स्थापना धार्मिक दीक्षा संस्कारों के लिए की गई थी। हालांकि इसकी स्थापना का प्रमाणित उद्देश्य आज तक कोई समझ नहीं पाया है। इस कुएं का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि इसके अंदर एक रोशनी नजर आती है, जो आमतौर पर संभव ही नहीं है, क्योंकि इस कुएं में रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बड़े-बड़े विद्वानों से लेकर वैज्ञानिक तक इस रहस्य को सुलझाने में अब तक नाकाम साबित हुए हैं। इस कुएं की गहराई किसी चार मंजिला इमारत के बराबर बताई जाती है। कहा जाता है कि इस कुएं में जितना ज्यादा जमीन के अंदर जाने की कोशिश की जाती है, कुआं उतना ही संकरा होता जाता है। यही सारे कारण हैं कि यह कुआं आज तक सभी के लिए एक रहस्य ही बना हुआ है।

एक ही दिन मैदान पर उतरेंगी भारत-पाक समेत चैंपियंस ट्रॉफी की 5 टीमें

इन 2 में से 1 पहुंचेगी फाइनल में

नई दिल्ली, एजेंसी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत-पाकिस्तान सहित कुल आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं. इनमें से पांच टीमें 12 फरवरी को एक ही दिन मैदान पर उतरने वाली हैं. ये सभी टीमें वनडे मैच खेलेंगी.

इनमें से दो टीमों के बीच ट्राई सीरीज के फाइनल में पहुंचने के लिए जंग होगी. वहीं दो टीमों के बीच मुकाबे में एक टीम अपनी साख बचाना चाहेगी जबकि दूसरी टीम उसका सूपड़ा साफ करना चाहेगी. तो चलिए देखते हैं ये पांच टीमें कौनसी है और 12 फरवरी को इनके मैच कहां और कितने बजे से खेले जाएंगे. भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मैच 12 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. टीम इंडिया शुरुआती दोनों मैच जीतने के बाद इंग्लैंड का क्लीन स्वीप करना चाहेगी. जबकि इंग्लैंड टीम आखिरी मैच जीतकर अपनी साख बचाना चाहेगी. अहमदाबाद में तीसरा वनडे दोपहर डेढ़ बजे से खेला जाएगा.

पहले वनडे में आमने-सामने होंगे ऑस्ट्रेलिया-श्रीलंका

श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया दो टेस्ट मैचों की सीरीज के बाद दो वनडे मैचों की सीरीज खेलने वाली हैं.

टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 से जीत ली है. अब पहले वनडे की शुरुआत 12 फरवरी को सुबह 10 बजे से कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होगी. ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा है, जबकि श्रीलंका इस ICC टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई थी.

ट्राई सीरीज के फाइनल के लिए होगी पाकिस्तान-साउथ अफ्रीका में जंग

12 फरवरी को ही पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमें भी वनडे मैच खेलेंगी. अभी न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच चार मैचों की एक ट्राई सीरीज पाकिस्तान में खेली जा रही है. सीरीज का पहला मैच पाक-न्यूजीलैंड के बीच 8 फरवरी को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में हुआ था जिसमें कीवी टीम को जीत मिली. इसी स्टेडियम में दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया और ट्राई सीरीज के फाइनल का टिकट कटा लिया. अब पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच बुधवार को कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में ढाई बजे से मैच खेला जाएगा. जो टीम इसमें जीत हासिल करेगी वो न्यूजीलैंड से 14 फरवरी को फाइनल में भिड़ेगी. फाइनल नेशनल बैंक स्टेडियम में ही होने वाला है.

नेशनल गेम्सः

किसान के बेटे का बड़ा कमाल, 19 साल की उम्र में तोड़ा नेशनल रिकॉर्ड

नई दिल्ली, एजेंसी। नेशनल गेम्स में कई युवा चेहरों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला है। कई खिलाड़ियों के लिए यह गेम्स करियर के लिहाज से ऐतिहासिक साबित हुए हैं। 19 साल के देव मीणा भी इसी फेहरिस्त में शामिल हैं जिन्होंने देहरादून में जारी नेशनल गेम्स में पोल वॉल्ट का नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा। किसान परिवार से आने वाले देव को देश के प्रतिशाली युवाओं में शुमार किया जाता है।

मध्य प्रदेश के देव कुमार मीणा ने सोमवार को पुरुष पोल वॉल्ट में 5.32 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड मेडल जीता। उन्नीस साल के देव ने 2023 के अपने खिताब का बचाव करते हुए स्वर्ण पदक जीता और एस शिवा के 5.31 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड में भी सुधार किया जो उन्होंने गुजरात में 2022 राष्ट्रीय खेलों के दौरान बनाया था। इससे पहले देव का निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5.20 मीटर था जो उन्होंने पिछले साल पटना में इंडिया ओपन अंडर-23 प्रतियोगिता जीतने के दौरान बनाया था।

देव को प्रतियोगिता से पहले ही यह महसूस हो रहा था कि 10 फरवरी की तारीख उनके करियर में बहुत अहम रहने वाली है। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि वह नेशनल गेम्स में इसी सोच के साथ आए थे कि उन्हें नेशनल रिकॉर्ड तोड़ना है और यही हुआ। एमपी स्पोर्ट्स अकेडमी के देव ने बताया कि वह शुरुआत में 400 मीटर इवेंट में हिस्सा लेते थे। उसी समय उनके मौजूदा कोच घनश्याम ने उन्हें देखा और पोल वॉल्ट के लिए मनाया। उन्होंने कहा, 'कोच साहब ने मुझे आश्वस्त किया कि मैं भविष्य में कुछ महान करूंगा और मुझे पोल वॉल्ट में जाना चाहिए क्योंकि मेरे हाथ बड़े हैं और मेरी पकड़ अच्छी है।' उन्होंने कहा, 'कोच साहब ने मुझसे कहा कि पोल वॉल्ट में बेहतर भविष्य होगा क्योंकि मेरे हाथ बड़े हैं और मेरी ग्रिप अच्छी है।' ट्रेनिंग शुरू होने के छह महीने तक कोच ने देव को किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेने दिया। वह चाहते थे कि देव पहले जंप करना सीखा और परिणाम के बारे में चाहते हैं। यह फैसला उनके लिए सही साबित हुआ।

इसी साल आईसीसी ट्रॉफी का इंतजार खत्म कर सकता है दक्षिण अफ्रीकाः स्मिथ

जोहानिसबर्ग, एजेंसी। पिछले साल सभी प्रारूपों में दक्षिण अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन से प्रभावित पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ को यकीन है कि अपनी मेजबानी में 2027 पुरूष वनडे विश्व कप खेलने से पहले ही वे आईसीसी ट्रॉफी के लिए लंबा चला आ रहा इंतजार खत्म कर देंगे। एसए 20 लीग कमिश्नर स्मिथ ने कहा, 'उम्मीद है कि हम चैम्पियंस ट्रॉफी या विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल जीतकर इस इंतजार को खत्म कर देंगे। लेकिन अगर दक्षिण अफ्रीका अपनी सरजमीं पर विश्व कप जीतता है तो यह शानदार होगा। महज 22 वर्ष की उम्र में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान बनने के बाद बतौर कप्तान 54 टेस्ट जीत दिलाने वाले इस दिग्गज ने कहा, 'अगले तीन साल में हम स्टेडियमों, पिचों और अपने क्रिकेट इकोसिस्टम को बेहतर करने के प्रयास जारी रखेंगे ताकि 2027 वनडे विश्व कप तक हम प्रबल दावेदार रहें। दक्षिण अफ्रीका ने सेंचुरियन में बॉक्सिंग डे टेस्ट में पाकिस्तान को हराकर डब्ल्यूटीसी फाइनल में प्रवेश किया जहां 11 से 15 जून तक लार्ड्स पर उसका सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका पुरूष और महिला टी20 विश्व कप और इस साल की शुरूआत में अंडर 19 महिला विश्व कप में उपविजेता रहा।

स्मिथ ने इन आलोचनाओं को भी खारिज किया कि डब्ल्यूटीसी फाइनल का दक्षिण अफ्रीका का सफर आसान रहा है। उन्होंने कहा, 'आजकल क्रिकेट में कोई सफर आसान नहीं होता। शुरू ही से सभी टीमों को पता था कि किसे किससे खेलना है। दक्षिण अफ्रीका ने लगातार सात टेस्ट जीतकर क्वालीफाई किया है। सभी को टेस्ट इकोसिस्टम देखना चाहिए कि वह कैसे काम करता है।

'क्लब बनाम देश की बहस पर स्मिथ का मानना है कि टी20 क्रिकेट का बढ़ना तय है लेकिन सभी सदस्य देशों को मिलकर ऐसा मॉडल बनाना होगा कि बाकी प्रारूप भी सुरक्षित रहें। दक्षिण अफ्रीका के लिए 117 टेस्ट में 9265 रन बना चुके स्मिथ ने कहा, 'मैं चाहता हूं कि टेस्ट क्रिकेट मजबूत रहे और अगर छह सात देशों में भी रह गया तो काफी प्रतिस्पर्धी होगा और मजबूत भी बना रहेगा।

दुनिया भर में शुरू हो रही फ्रेंचाइजी आधारित टी20 लीग के बीच टेस्ट क्रिकेट के अस्तित्व को बचाये रखने के सवाल पर उन्होंने कहा, 'टी20 क्रिकेट ने अमेरिका और दूसरे क्षेत्रों में नये दर्शक दिए हैं और अब हम इसे ओलंपिक में भी देखेंगे। इसने काफी दर्शक बनाए हैं। मुझे लगता है कि फ्रेंचाइजी आधारित क्रिकेट में आखिर में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ तीन चार लीग बचेंगी और शायद एक टू टियर सिस्टम। भविष्य में सभी सदस्य देशों को साथ मिलकर एक दूसरे को मजबूत रखना होगा।

स्नूकर चैंपियनशिपः

पंकज आडवाणी ने जीती राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप, करियर का 36वां राष्ट्रीय खिताब जीता

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत के अनुभवी और स्टार स्नूकर खिलाड़ी पंकड आडवाणी ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली है। पंकज के करियर का यह कुल 36वां राष्ट्रीय और 10वां पुरुष स्नूकर खिताब है। ओएनजीसी की तरफ से खेल रहे आडवाणी ने खराब शुरुआत से उबरते हुए फाइनल में ब्रिजेश दमानी को हराया।

दमानी ने पहला फ्रेम जीत कर अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन इसके बाद आडवाणी के सामने उनकी एक नहीं चली। इस प्रतियोगिता के प्रदर्शन के आधार पर ही एशियाई और विश्व चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम का चयन किया जाएगा। आडवाणी ने अपने प्रदर्शन में निरंतरता और सटीकता बनाए रखी। एक फ्रेम से पिछड़ने के बावजूद उन्होंने अपना धैर्य बनाए रखा और फिर कोई गलती नहीं की। आडवाणी ने अंतिम फ्रेम में 84 का प्रभावशाली ब्रेक दिया तथा यह फ्रेम, मैच और चैंपियनशिप अपने नाम कर दी।

एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप में खेलेंगे पंकज-दमानी

दमानी ने ग्रुप चरण में आडवाणी को हराया था लेकिन फाइनल में वह इस अनुभवी खिलाड़ी के खिलाफ अपनी लय बरकरार नहीं रख पाए। दमानी के खिलाफ ग्रुप चरण के मैच में आडवाणी केवल एक फ्रेम जीतने में सफल रहे थे। एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 15 फरवरी से शुरू होगी जिसमें आडवाणी और दमानी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।

आडवाणी ने चैंपियनशिप जीतने के बाद कहा, यह एकमात्र प्रतियोगिता थी जिसके प्रदर्शन के आधार पर अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधियों का चयन किया जाएगा। इसलिए इस प्रतियोगिता में काफी कुछ दाव पर लगा था। यहां स्वर्ण पदक जीत कर बहुत अच्छा लग रहा है। प्रतियोगिता में एक समय मैं बाहर होने के कगार पर था। तब मुझे पता चला कि इस महत्वपूर्ण क्षण का मतलब कुछ बड़ा होना चाहिए। बिलियर्ड्स और स्नूकर दोनों में फिर से भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका पाकर खुश हूं।

उर्विल पटेल ने रणजी ट्रॉफी में भी शतक जड़ा

नई दिल्ली, एजेंसी। गुजरात के उर्विल पटेल के लिए यह रिकॉर्ड सीजन रहा है। हीरे के पर्याय माने जाने वाले पालनपुर शहर में क्रिकेट की शुरुआत करने वाले 26 वर्षीय उर्विल पटेल ने दिखाना शुरू कर दिया है कि वह शहर से निकलने वाले सबसे तराशे हुए रत्न क्यों हैं। इस सीजन की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने 28 गेंदों पर किसी भारतीय द्वारा बनाया गया सबसे तेज टी20 शतक जड़ा, जो दुनिया में दूसरा सबसे तेज शतक है।

पिछले सीजन की विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने 41 गेंदों पर शतक जड़ा था, जो किसी भारतीय द्वारा बनाया गया दूसरा सबसे तेज शतक था। उर्विल ने रिकॉर्ड बुक में फिर से नाम दर्ज करने करते हुए रणजी ट्रॉफी में सौराष्ट्र के खिलाफ अपने पहले प्रथम श्रेणी शतक (197 गेंदों पर 140 रन) के साथ श्रेयस अय्यर के बाद एक ही घरेलू सीजन में तीनों प्रारूपों में शतक बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए।

बुमराह भारत के रोनाल्डो हैं, जब तक जरूरत न हो, उन्हें नहीं बदल सकतेः इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज

नई दिल्ली, एजेंसी। इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टीव हार्मिसन ने भारत के शीर्ष तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और फुटबॉल सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बीच एक शानदार समानता दर्शाते हुए तेज गेंदबाज की अपूरणीय प्रकृति पर जोर दिया है। हार्मिसन का मानना ??है कि अगर बुमराह चोट के कारण आगामी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाते हैं, तो यह रोनाल्डो के बिना फीफा विश्व कप जैसा होगा।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की टेस्ट सीरीज में अहम भूमिका निभाने वाले बुमराह अपनी पीठ की सूजन से जूझ रहे हैं और उनके चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप चरण से बाहर होने की संभावना है। हालांकि हार्मिसन ने जोर देकर कहा कि भारत को नॉकआउट दौर के लिए उनकी वापसी की उम्मीद में उन्हें आखिरी क्षण तक टीम में रखना चाहिए। हार्मिसन ने अपने प्रमुख तेज गेंदबाज के साथ भारत के धैर्य के लिए एक आकर्षक तर्क दिया। उन्होंने कहा, वह जसप्रीत बुमराह है। मेरे हिसाब से आप कभी भी जसप्रीत बुमराह की जगह नहीं ले सकते। और मेरा मतलब है, मैं उसे इतना आगे ले जाने के लिए फाइनल की सुबह तक भी जा सकता हूं क्योंकि वह जसप्रीत बुमराह है। वह दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। भारतीय दृष्टिकोण से मेरा यही मानना है।

गिलक्रिस्ट ने पोंटिंग से असहमति जताई, वॉर्न को अब तक का सबसे महान क्रिकेटर घोषित किया

नई दिल्ली, एजेंसी। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के दिग्गज एडम गिलक्रिस्ट ने महानतम ऑलराउंडर की बहस में अपना पक्ष रखा है, उन्होंने रिकी पोंटिंग के इस दावे को चुनौती दी है कि जैक्स कैलिस अब तक के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर हैं। जबकि पोंटिंग ने हाल ही में कैलिस की बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन के लिए प्रशंसा की, गिलक्रिस्ट का मानना है कि केवल आंकड़े ही महानता को परिभाषित नहीं करते हैं और इसके बजाय उन्होंने दिवंगत शेन वॉर्न को क्रिकेट के सर्वकालिक शीर्ष खिलाड़ियों में शीर्ष पर रखा। एक साक्षात्कार में गिलक्रिस्ट ने कहा, मैं समझता हूं कि रिकी किस बात पर जोर दे रहे हैं - आंकड़ों के हिसाब से, रन, विकेट और कैच - लेकिन इसमें सिर्फ आंकड़ों से कहीं अधिक है।मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि शेन वॉर्न अब तक खेले गए सबसे महान खिलाड़ी हैं।

टॉक्सिक की शूटिंग दो भाषाओं में कर रहीं कियारा आडवाणी, बेंगलुरु में चल रहा फिल्म पर काम

कियारा आडवाणी अपनी पहली द्विभाषी फिल्म टॉक्सिक की शूटिंग अंग्रेजी और कन्नड़ दोनों भाषाओं में कर रही हैं। इन दिनों फिल्म की शूटिंग बेंगलुरु में हो रही है। अभिनेत्री कियारा आडवाणी इन दिनों अपनी पहली कन्नड़ फिल्म टॉक्सिक की शूटिंग में व्यस्त हैं। फिल्म के निर्देशन की कमान राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक गीता मोहनदास के हाथों में है। यह फिल्म एक हाई-ऑक्टेन एक्शन गैंगस्टर ड्रामा है, जिसे अंग्रेजी और कन्नड़ दोनों भाषाओं में एक साथ शूट किया जा रहा है। बीते काफी समय से कियारा का करियर कुछ खास नहीं चल रहा है। ऐसे में टॉक्सिक से उन्हें काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। इस फिल्म को लेकर वह काफी ज्यादा मेहनत भी कर रही हैं।

साहस, एकता और शिक्षा की मजबूत कहानी है 'रूल ब्रेकर्स' : अली फजल

अभिनेता अली फजल की अपकमिंग फिल्म 'रूल ब्रेकर्स' 7 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से पहले अमेरिका में रिलीज के लिए तैयार है। अभिनेता ने बताया कि फिल्म में साहस, एकता और शिक्षा की एक मजबूत कहानी है। अभिनेता ने अपने किरदार के पहले लुक की झलक शेयर की। फिल्म में अली लॉस एंजिल्स के एक तकनीकी विशेषज्ञ की भूमिका में नजर आएंगे।

फिल्म में उनके किरदार का नाम समीर सिन्हा है। अपनी उत्सुकता को शेयर करते हुए अली ने कहा, यह फिल्म एक रत्न है और मैं इसका हिस्सा बनकर गर्व महसूस कर रहा हूं। 'रूल ब्रेकर्स' सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह साहस, एकता और शिक्षा के साथ बनी एक मजबूत कहानी है। उन्होंने कहा, अमेरिका में महिला दिवस की पूर्व संध्या पर रिलीज करना इसे और भी खास बनाता है क्योंकि यह महिलाओं की ताकत के साथ जुड़ा है। मैं फिल्म की रिलीज को लेकर उत्साहित हूं। मनोरंजक-ड्रामा 'रूल ब्रेकर्स' महिला-केंद्रित फिल्म है और एक ऐसी महिला की कहानी बताती है, जो ऐसे समाज में युवा लड़कियों को शिक्षित करने का साहस करती है, जहां इसे एक विद्रोह के रूप में देखा जाता है। 'रूल ब्रेकर्स' का निर्देशन ऑस्कर विजेता फिल्म निर्माता बिल गुटेंटैग ने किया है।

इस बीच बता दें, 2025 काम के लिहाज से अली के लिए बेहद खास साल है।

मुझे नहीं लगता इसके लिए उन्हें जेल होनी चाहिए

विवाद के बीच समय रैना के बचाव में आईं उर्फी

उर्फी जावेद कथित दोस्त के बचाव में आई हैं।

समय रैना के शो इंडियाज गॉट लैटेंट में अभद्र टिप्पणी को लेकर रणवीर इलाहाबादिया विवादों में हैं। समय रैना पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस बीच उर्फी जावेद कथित फ्रेंड समय रैना के बचाव में आई हैं।

मशहूर यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने हाल ही में समय रैना के शो इंडियाज गॉट लैटेंट में परिवार को लेकर अश्लील टिप्पणी की। उन्होंने जो कुछ भी कहा, उस पर विवाद हो रहा है। रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना सहित कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। रणवीर की अलोचना हो रही है तो समय रैना पर भी सवाल उठ रहे हैं। यूट्यूब पर आपत्तिजनक कंटेंट दिखाने के लिए समय को जेल भेजने की मांग की जा रही है। इस पर

जेल नहीं भेजना चाहिए

समय रैना के शो इंडियाज गॉट लैटेंट को यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया के साथ पिछले एपिसोड को लेकर कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। शो में कथित तौर पर अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल को लेकर दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना की जमकर आलोचना हो रही है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उर्फी जावेद कहा है, भले ही पैनल पर इस तरह की टिप्पणियां की गईं, जो आपत्तिजनक थीं, लेकिन इसके लिए उन्हें जेल नहीं भेजना चाहिए।

उन लोगों को आकर्षित करें जो आपकी भाषा समझते हों, मनीषा कोइराला ने शेयर किया पोस्ट

अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने सोशल मीडिया पर एक विचार भरा पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि हमें उन लोगों को आकर्षित करना चाहिए, जो आपकी भाषा समझते हैं। स्टोरीज सेक्शन पर पोस्ट शेयर करते हुए अभिनेत्री ने लिखा, आप ऐसे लोगों को आकर्षित करें जो आपकी भाषा बोलते हों, ताकि आपको अपनी भावनाओं को समझाने के लिए जीवन भर अनुवाद करने की जरूरत ना पड़े। सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी के कई हिस्से दिखाने वाली अभिनेत्री मनीषा कोइराला अक्सर दोस्तों और परिवार के साथ आनंद भरे पल बिताती नजर आती हैं। दोस्तों के साथ उनका खास रिश्ता है। अभिनेत्री अक्सर खूबसूरत वादियों के बीच दोस्तों संग छुट्टियां मनाती नजर आती हैं।

संक्षिप्त समाचार

'शीशमहल' में मिलाई गई संपत्तियों को अलग करें; भाजपा की उपराज्यपाल से मांग

नईदिल्ली, एजेंसी। दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक विजेंदर गुप्ता ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से शीशमहल में मिलाई गई संपत्तियों को अलग करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कई ऐसी प्रापर्टी थीं जो अधिकारियों और बाकी लोगों के के रहने के लिए थी। केजरीवाल जी ने 6 फ्लैग स्टाफ रोड को 10 से 50 हजार गज बनाने के लिए इसमें मर्ज (मिला) कर लिया था। गुप्ता ने कहा, मैंने मांग की है कि शीश महल में विलय की गई संपत्तियों को अलग किया जाना चाहिए। दिल्ली सरकार के अधिकारियों की 10 संपत्तियों का विलय कर दिया गया। केजरीवाल ने इसे 10,000 गज से 50,000 गज की संपत्ति में बदल दिया। हमने मांग की है कि एलजी इन संपत्तियों को अलग करें। इनमें जो तमाम संपत्तियां हैं उन्हें रीस्टोर किया जाए। दिल्ली सरकार के पास जो सरकारी निवास की दिक्कत रहती है, जिसे आम आदमी पार्टी ने बढ़ा दिया था। उसे वापस पूल में लाया जाए। इससे पहले सोमवार को उन्होंने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से चार संपत्तियों का 'शीशमहल' (6, फ्लैगस्टाफ रोड) के साथ विलय रद्द करने का अनुरोध किया था। भाजपा ने 'शीशमहल' का इस्तेमाल हालिया विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के मुद्दों पर घेरने के लिए एक राजनीतिक हथियार के रूप में किया। गुप्ता ने कहा कि बंगले का विस्तार चार सरकारी संपत्तियों को मिलाकर किया गया है और उन्होंने उन संपत्तियों के विलय को रद्द करने के लिए उपराज्यपाल सक्सेना को एक पत्र लिखा है। सिविल लाइंस क्षेत्र में 6, फ्लैगस्टाफ रोड स्थित पुनर्निर्मित बंगला 2015 से अक्टूबर 2024 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल का आधिकारिक निवास था। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों पर पद से इस्तीफा देने के बाद इसे खाली कर दिया था।

भाई-बहन को भी मुश्किल में एक-दूसरे का साथ देने का कानूनी हक, दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

नईदिल्ली, एजेंसी। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने तीन बहनों को 58 वर्षीय बीमार भाई से मिलने देने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि माता-पिता, औलाद और पति-पत्नी के संबंधों की तरह ही भाई-बहन को एक-दूसरे का हालचाल पता करने व मुश्किल में साथ देने का कानूनी हक है। इसे रोका नहीं जा सकता। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस धर्मेश शर्मा की बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि यहां तीन बहनें अपने भाई के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। उन्हें डर है कि उनकी भाभी और भतीजा उनके भाई को पागल घोषित करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें उनके भाई से मिलने नहीं दिया जा रहा है। इस मामले में पीड़ित की मां ने भी बेटे से मिलने की इच्छा जाहिर की है। वहीं, प्रतिवादी भाभी और भतीजे ने बेंच के समक्ष 58 वर्षीय व्यक्ति की बीमारी से संबंधित दस्तावेज पेश किए, जिसके हिसाब से पीड़ित विमहंस अस्पताल में भर्ती है। बेंच ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मानव व्यवहार और संबद्ध विज्ञान संस्थान (इहबास) के निदेशक के नेतृत्व में मेडिकल बोर्ड गठित करने के निर्देश दिए थे। अनुमति दी है, वहीं बहनों को भी चेताया है कि उनकी यह मुलाकात सौहार्दपूर्ण होनी चाहिए।

दिल्ली में सुबह-शाम ठंड, दिन में गर्मी कर रही परेशान

नईदिल्ली, एजेंसी। दिल्ली में मौसम के दो रंग देखने को मिल रहे हैं। सुबह-शाम ठंड का अहसास हो रहा है जबकि दिन में गर्मी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों ऐसा ही मौसम रहेगा। राजधानी में सोमवार को दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में अधिकतम तापमान सामान्य से साढ़े चार डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। अगले दो दिनों के बीच भी मौसम का यही रुख बना रहेगा। दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में सोमवार की सुबह हल्की धुंध देखने को मिली, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही धूप निकल गई। इससे अधिकतम तापमान में इजाफा हुआ है।

दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस कम है। यहां पर आर्द्रता का स्तर 97 से 27 फीसदी के बीच रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि मंगलवार को अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री के बीच और न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। इस दौरान हवा की गति आठ से 12 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अनुमान है।

दिल्ली की हवा लगातार खराब श्रेणी में बनी हुई है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, सोमवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 271 के अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को खराब श्रेणी में रखा जाता है। अगले दो दिनों के बीच भी वायु गुणवत्ता का स्तर इसी के आसपास रहने की संभावना है। दिल्ली के 37 में से आठ निगरानी केंद्रों में प्रदूषण स्तर में सुधार हुआ है। सबसे ज्यादा सुधार डीटीयू में दर्ज किया गया। यहां 26 फीसदी प्रदूषण कम हुआ है। एनएसआईटी द्वारका में 22 फीसदी का सुधार हुआ है।

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार, मंगलवार को आसमान साफ रहेगा। बुधवार,गुरुवार और शुक्रवार को साफ आसमान के चलते गर्मी का अहसास होगा। शनिवार को आसमान में बादलों का डेरा रहेगा। इसके बाद रविवार को मौसम साफ रहेगा। वहीं सोमवार को बादलों की आवाजाही बनी रहेगी।

चूड़ियां नहीं पहनी हैं, जब तक जिंदा हूं...; मुस्तफाबाद को शिव का नाम देने के ऐलान पर आप के हाजी यूनुस ने कहा

नईदिल्ली, एजेंसी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बाद मुस्तफाबाद को लेकर घमासान छिड़ गया है। 40 फीसदी से अधिक मुस्लिम आबादी वाली सीट से जीत हासिल करने वाले भाजपा नेता मोहन सिंह बिष्ट ने इसका नाम बदलने का वादा किया है। चुनाव प्रचार के दौरान और जीत के बाद उन्होंने ऐलान किया कि मुस्तफाबाद का नाम बदल शिव विहार या शिव पुरी कर दिया जाएगा। अब इसका विरोध शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी यूनुस ने कहा है कि जब तक वह जिंदा हैं ऐसा नहीं होने देंगे।

मोहन सिंह बिष्ट की ओर से यह कहे जाने पर कि मुस्तफाबाद में 42 फीसदी नहीं, 58 फीसदी की चलेगी, हाजी यूनुस ने कहा, यहां 42 फीसदी नहीं, इस बार यहां 48.9 फीसदी मुस्लिम हैं। एक तो उनको अपनी जानकारी दुरुस्त कर लेनी चाहिए, वोटर लिस्ट देख लेनी चाहिए कि मुसलमान कितना है। पूर्व विधायक ने कहा, रहा सवाल नाम बदलने का तो मुस्तफाबाद का नाम तो मुस्तफाबाद ही रहेगा। वह कितना भी चाह लें यह नहीं बदला जाएगा।

हाजी ने एक चैनल से बातचीत का वीडियो एक्स पर शयेर करते हुए लिखा, जब तक में जिंदा हूं मुस्तफाबाद का नाम नहीं बदला जाएगा, मुस्तफाबाद का नाम मुस्तफाबाद ही रहेगा। पूर्व विधायक ने वीडियो में कहा, अगर उन्हें इतनी फिक्र थी शिव विहार की तो अभी एमसीडी इलेक्शन से पहले एलजी साहब ने, भाजपा ने शिव विहार का नाम बदल ईस्ट करावल नगर कर दिया। वह तो शिव विहार का नाम नहीं बचा सके, मुस्तफाबाद का नाम क्या बदलेंगे। अभी मुस्तफाबाद की आवाम ने चूड़ियां नहीं पहनी हैं। इस तरह से मुस्तफाबाद का नाम कैसे बदल जाएगा। आप नेता ने कहा, 2026 में जो परिसीमन होने जा रहा है और एक विधानसभा की सीट बढ़ाई जाएगी उसमें वह ईस्ट करावल नगर वार्ड को अलग करके चाहे शिव पुरी रखें या कुछ भी रखें। मुस्तफाबाद का नाम मुस्तफाबाद ही रहेगा, यह हमारे जीते जी कभी नहीं बदलेगा।

दुष्कर्म और सहमति से बने यौन संबंधों में अंतर करने की जरूरत, दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी को दी जमानत

नईदिल्ली, एजेंसी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित बलात्कार के मामले में सोमवार को एक व्यक्ति को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि बलात्कार व सहमति से बने शारीरिक संबंधों के बीच अंतर करना जरूरी है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि जहां कार्यबल में महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण के लिए कानून बनाना और उन्हें लागू करना विधायिका और कार्यपालिका का कर्तव्य है, वहीं कोर्ट का ÷प्रहरी÷ बनना और इसके दुरुपयोग को रोकना ÷कठिन कर्तव्य÷ है। अदालत ने कहा, वर्तमान समय में, कई बार कार्यस्थल पर निकटता के कारण सहमति से संबंध बनते हैं, जो खराब होने पर अपराध के रूप में रिपोर्ट किए जाते हैं, इसलिए बलात्कार के अपराध और दो वयस्कों के बीच सहमति से बने यौन संबंध के बीच अंतर के प्रति सचेत होना उचित है।

आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि यह मामला उसी श्रेणी में आता है, जिसमें पुरुष और महिला के बीच एक ही कार्यस्थल पर ÷यौन निकटता÷ विकसित की थी, लेकिन लगभग एक साल के बाद रिश्ते में खटास आ गई और ÷बल प्रयोग और बलात्कार÷ के आरोप लगने लगे। अदालत ने मई 2024 में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को लंबे समय तक सलाखों के पीछे रखने का कोई फायदा नहीं देखा। हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में आरोप तय किए गए थे और आरोपों की सत्यता की जांच मुकदमे के दौरान की जानी चाहिए, जिसमें कुछ समय लगने की संभावना है। आरोपी व्यक्ति ने अपनी याचिका में ऐसा दावा किया कि दोनों पक्षों ने काफी लंबे समय तक÷ एक-दूसरे को डेट किया और एक-दूसरे के प्रति गहरे प्यार में थे।

पत्नी-बेटी को जेल में डाल देंगे, एलआईसी के रिटायर मैनेजर से 1.10 करोड़ ठगे

पूरे परिवार को किया डिजिटल अरेस्ट

नईदिल्ली, एजेंसी। साइबर अपराधियों ने धन शोधन केस में फंसाने की धमकी देकर एलआईसी के सेवानिवृत्त प्रबंधक को पूरे परिवार समेत पांच दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर एक करोड़ 10 लाख रुपये हड़प लिए। ठगी की जानकारी होने के बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत साइबर क्राइम थाने की पुलिस से की। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

सेक्टर-19 के ए ब्लॉक में रहने वाले चंद्रभान पालीवाल ने बताया कि एक फरवरी को दोपहर दो बजकर 40 मिनट पर उनके मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आई। कॉलर ने उनसे तुरंत ट्राई से संपर्क करने को कहा। ऐसा न करने पर दो घंटे के भीतर सिम बंद होने की धमकी भी दी। इसके बाद बताया कि उनका मामला मुंबई साइबर क्राइम ब्रांच के पास है। करीब दस मिनट बाद मुंबई के

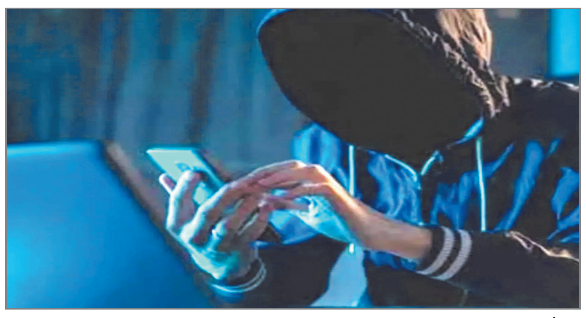

कोलावा पुलिस स्टेशन से एक व्यक्ति की कॉल आई। उसने खुद को आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार बताया। राजीव द्वारा की गई वीडियो कॉल में ग्रेटर मुंबई पुलिस का लोगो दिखाई दे रहा था। कथित आईपीएस ने चंद्रभान से कहा कि उनके खिलाफ अलग-अलग जगहों पर 24 केस दर्ज हैं। उन पर लोगों को डरा-धमकाकर रुपये वसूलने का आरोप कथित आईपीएस अधिकारी ने लगाया। कथित अधिकारी ने बताया कि चंद्रभान के खिलाफ सीबीआई में धन शोधन का केस है। अधिकारी ने खुद को ही केस का जांच अधिकारी बताया। ठग ने कहा कि चंद्रभान के नाम से केनरा बैंक मुंबई में एक बैंक खाता खोला गया है। उस बैंक से रुपये निकालकर चंद्रभान के खाते में डाला गया। सारी रकम मनी लॉन्ड्रिंग की है। उनको यह भी बताया कि जिस सिम से धमकाकर लोगों से पैसा वसूला गया है, वह सिम चंद्रभान के नाम से ही है।

इतना सब कुछ सुनकर वह डर गए। ठगों ने डराने के लिए उनसे यह भी कहा कि उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट है। उसकी तुरंत गिरफ्तारी होगी और मुंबई साइबर क्राइम सेल के सामने पेश किया जाएगा। आधार कार्ड की जांच के लिए कैमरे को सामने लाकर फोटो लिया गया। इस दौरान पीड़ित से बैंक संबंधी जानकारी भी ली गई। जांच रिपोर्ट सीबीआई को भेजने की बात ठगों द्वारा कही गई। इसके बाद एक सीबीआई के अधिकारी की कॉल पीड़ित के पास आई। उसके द्वारा बताया गया कि धन शोधन केस में पीड़ित के ही आधार कार्ड का इस्तेमाल हुआ था। इतना सब कुछ होने के बाद ठगों ने कहा कि सोमवार को पीड़ित का केस सीबीआई कोर्ट में रखा जाएगा। उनकी पत्नी और बेटी का नंबर भी ठगों ने इस दौरान पूछ लिया। अनजान और किसी अन्य व्यक्ति की कॉल जांच पूरी होने तक न उठाने की हिदायत शिकायतकर्ता और उसके परिवार को दी गई। मामला नरेश गोयल के साथ जुड़ा होने के कारण पीड़ित, उसकी पत्नी और बेटी को अलग-अलग जेल में डालने की धमकी दी गई। पूरी रात स्काइप कॉल के जरिये परिवार पर नजर रखी गई। अगले दिन सीबीआई कोर्ट में एक व्यक्ति जज के रूप में दिखाया गया।

अब ब्रिटेन में ट्रंप जैसा ऐक्शन, 19 हजार प्रवासी बाहर किए; मारे जा रहे देश भर में छापे

लंदन, एजेंसी। अमेरिका ने हाल ही में ब्राजील, भारत, मेक्सिको समेत कई देशों के अवैध प्रवासियों को बाहर निकाला है। अब बिना दस्तावेज के आए प्रवासियों और अपराधियों के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप जैसा ही ऐक्शन ब्रिटेन में भी शुरू हुआ है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के सत्ता में आने के बाद से करीब 19000 अवैध प्रवासियों और अपराधियों को देश से बाहर कर गया है। इन लोगों को डिपोर्ट करने का एक वीडियो भी ब्रिटिश सरकार की ओर से जारी किया गया है। पूरे देश में ही अवैध प्रवासियों के खिलाफ यह अभियान चलाया गया है। इसके लिए छापेमारी की गई है, जिसमें बड़ी संख्या में अवैध प्रवासी पाए गए। इन लोगों को डिपोर्ट किया गया है।

इस अभियान के तहत भारतीय रेस्तरां, नेल बार, स्टोर और कार वॉश में छापेमारी की गई है। इनमें बड़ी संख्या में अवैध प्रवासियों को काम पर रखे जाने की शिकायतें मिली थीं। ब्रिटिश होम मिनिस्टर वेटे कूपर ने कहा कि उनके विभाग ने जनवरी में बड़े पैमाने पर छापेमारी की है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद से कुल 19000 लोगों को डिपोर्ट किया गया है। जनवरी महीने में ही 828 परिसरों पर रेड मारी गई है और 609 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बीते साल की जनवरी के मुकाबले यह 73 फीसदी ज्यादा नंबर था। 7 लोगों को तो अकेले हंबरसाइड स्थित भारतीय रेस्तरां में छापा मारकर अरेस्ट किया गया। इसके अलावा 4 को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा ब्रिटिश संसद में नया बिल भी पेश किया गया है। इस विधेयक में सीमा सुरक्षा, शरण और अवैध प्रवासियों को बाहर करने का प्रस्ताव रखा गया है। ब्रिटिश सांसदों का कहना है कि इस विधेयक को लाने से बड़ी संख्या में आपराधिक गैंगों को खत्म करने में मदद मिलेगी। पीएम कीर स्टारमर की सरकार का कहना है कि पूर्व की सरकारों ने सीमा सुरक्षा से समझौता किया था। अब इस पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। ब्रिटिश सरकार ने उन संस्थानों को भी फाइल लगाने का फैसला लिया है, जो अवैध प्रवासियों को नौकरी देंगे। ऐसे मामलों में प्रति व्यक्ति 60 हजार पाउंड का फाइन लगाने का फैसला लिया गया है। अब तक कुल 1000 नोटिस जारी किए गए हैं। बीते साल जुलाई में हुए आम चुनाव के बाद से ही अब तक 16,400 लोगों को बाहर किया जा चुका है।

निर्वासितों के साथ इंसानियत का व्यवहार होना चाहिए, भारतवंशी अमेरिकी सांसद की अपनी सरकार से अपील

वॉशिंगटन, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे और दोनों देशों के कुछ अहम मुद्दों पर भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने बात की। उन्होंने अपनी सरकार से अपील की कि निर्वासित किए जा रहे लोगों के साथ इंसानियत वाला व्यवहार किया जाना चाहिए। रो खन्ना ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की आगामी मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच अवैध अप्रवासियों के मुद्दे पर बातचीत हो सकती है। अवैध अप्रवासियों को निर्वासित किए जाने पर रो खन्ना ने कहा कि मेरा मानना है कि अगर निर्वासन होता है तो वो इंसानी तरीके से होना चाहिए और लोगों के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार होना चाहिए। उनका अमानवीय तरीके से उत्पीड़न नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बेशक, अमेरिका आने वाले लोगों को कानूनी तरीके से ही अमेरिका आना चाहिए और कानून का पालन करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये मुद्दा जल्द सुलझ जाएगा। रो खन्ना ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार असंतुलन का भी मुद्दा है। अमेरिका का चीन, कनाडा और यूरोप के साथ भी व्यापार असंतुलन है। इनमें अमेरिका ज्यादा सामान खरीदता है, लेकिन ये देश अमेरिका से कम सामान खरीदते हैं। भारत के साथ भी अमेरिका का व्यापार असंतुलन है। रो खन्ना ने कहा कि इस व्यापार असंतुलन को खत्म किया जाना चाहिए।

बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मस्कट में एस जयशंकर से कर सकते हैं मुलाकात : रिपोर्ट

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश में मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन जल्द विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात कर सकते हैं। दोनों नेताओं की मुलाकात अगले सप्ताह मस्कट में आयोजित होने वाले हिंद महासागर सम्मेलन के दौरान हो सकती है। यह जानकारी सोमवार को ढाका की स्थानीय मीडिया ने दी। बांग्लादेश के प्रमुख बंगाली दैनिक प्रोथोम एलो ने बताया, राजनयिक सूत्रों के अनुसार, इस बैठक के दौरान बांग्लादेश दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव को रोकने के उद्देश्य से एक संदेश देना चाहेगा। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 16-17 फरवरी को मस्कट, ओमान में होगा। इसका आयोजन ओमान के विदेश मंत्रालय के सहयोग से इंडिया फाउंडेशन कर रहा है। इस वर्ष सम्मेलन का विषय, समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा है।

विदेश मंत्री जयशंकर और हुसैन की पिछली मुलाकात सितंबर में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान हुई थी। यह अगस्त 2024 में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद से हटने के बाद भारत और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के बीच पहली उच्च स्तरीय बातचीत थी। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद से भारत दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। वहीं ढाका की वर्तमान सरकार बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय को सुरक्षा नहीं देने के कारण आलोचना का शिकार होना पड़ रहा है।

बता दें पिछले वर्ष 5 अगस्त को छात्रों के उग्र विरोध प्रदर्शन की वह हसीना की अवामी लीग सरकार का नाटकीय ढंग से पतन हो गया था। शेख हसीना के देश छोड़कर भागने के बाद से अल्पसंख्यक समुदायों को लगातार निशाना बनाने की खबरें आ रही हैं। दिसंबर में विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने एक दिवसीय यात्रा पर ढाका का दौरा किया और अंतरिम सरकार के शीर्ष नेतृत्व को नई दिल्ली की चिंताओं, विशेष रूप से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कल्याण से संबंधित चिंताओं से अवगत कराया।

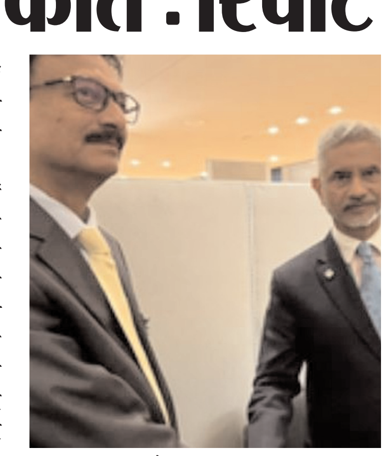

विवादों में रहने वाले कान्ये वेस्ट को एक्स पर किया बैन

वाशिंगटन, एजेंसी। सोशल मीडिया पर कान्ये वेस्ट के हालिया व्यवहार ने उनके प्रशंसकों और आम जनता के बीच चिंता पैदा कर दी है. अमेरिकी रैपर और बिजनेसमैन कान्ये वेस्ट को ये के नाम से जाना जाता है. आपको बता दें कि बिजनेसमैन कान्ये वेस्ट को एलन मस्क की एक्स से बैन कर दिया गया है.

शॉपिफाई पर बिक्री के लिए स्वस्तिक शर्ट को सूचीबद्ध करने से लेकर, यहूदियों और टेलर स्विफ्ट के खिलाफ घृणा से भरे भाषणों, सीन डिड्डी कॉम्ब्स का समर्थन करने वाले पोस्ट, ऑटिज्म को अजीब होने का कारण बताना, पत्नी बियांका सेंसरी की तस्वीरें पोस्ट करना और बहुत कुछ के कारण कान्ये वेस्ट के एक्स खाते को कथित तौर पर एलोन मस्क द्वारा बैन कर दिया गया है.

वेस्ट का एक्स अकाउंट उनके बेबाक विचारों का मंच बन गया, जिसके कारण उनकी व्यापक आलोचना हुई. उन्होंने यहूदी विरोधी और नस्लवादी टिप्पणियों सहित कई विवादास्पद बयान पोस्ट किए. आपको बता दें कि 10 फरवरी को कान्ये वेस्ट का एक्स प्रोफाइल पर यह मैसेज दिखा कि यह अकाउंट मौजूद नहीं है. इसके अलावा 11 फरवरी की सुबह एक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर अकाउंट करने पर भी यह खाता नहीं दिखा. हालांकि वेस्ट की ऑनलाइन गतिविधियों में गिरावट आई है, जिसके कारण कई लोगों ने उनके मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठाए हैं. हाल ही में पॉडकास्ट में, वेस्ट ने दावा किया कि वह बाइपॉलिटरी से नहीं, बल्कि ऑटिज्म से पीड़ित है. कान्ये के एक्स पोस्ट की ओर इशारा करते हुए एक यूजर की पोस्ट का जवाब देते हुए मस्क ने लिखा कि उसने जो पोस्ट किया है, उसके आधार पर उसका अकाउंट अब एनएसएफडब्ल्यू के रूप में वर्गीकृत है. आपको अब ऐसा नहीं देखना चाहिए. यहां एनएसएफडब्ल्यू का मतलब है काम के लिए सुरक्षित नहीं माना गया, टेक अरबपति ने ट्विटर पर कान्ये को अनफॉलो भी कर दिया.

स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रकः- देवेन्द्र मालवीय द्वारा श्री सिंध्दी विनायक प्रिंटर्स 26 बी देशबंधु परिसर प्रेस काम्प्लेक्स झोन 1 एम पी नगर भोपाल म.प्र. से मुद्रित एवं 773 / 19 मेघदूत नगर इंदौर म.प्र. से प्रकाशित सम्पादक डॉ. देवेन्द्र मालवीय

कार्यालय पताः-एच. 21 अकिंत अपार्टमेंट ब्रजेश्वरी एनएक्स, इंदौर मध्यप्रदेश मोः- 98276-22204 सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र इंदौर रहेगा। डाक पंजीकरण संख्या-MP/IDC/1619/2024-2026

दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त सूचनाए, विचार,आलेख विभिन्न समाचार के स्त्रोत एवं संकलन लेखकों के व संकलनकर्ता के स्वंय जिनका संकलन विभिन्न एजेंसियों, के माध्यम से किया गया है, अतः समस्त प्रकार के प्रकाशन हेतु संपादक, प्रकाशक, मुद्रक का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहमत होना अनिवार्य नही है।